



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938
No. 213] NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ASADHA 13, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

अंतिम जांच परिणाम

विषय: जापान और थाइलैंड के मूल अथवा वहां से निर्यातित फिनोल के आयातों संबंधी निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) पाटनरोधी जांच।

सं. 15/05/2015 डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान) उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

- उपरोक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 11 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या 24/27/2009-डीजीएडी के तहत जापान और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल के आयात से संबंधित मूल जांच शुरू की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 03 फरवरी, 2010 को अंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक परिणाम अधिसूचित किए थे। अंतिम शुल्क 19 अप्रैल, 2010 को लगाए गए थे। प्राधिकारी द्वारा अंतिम परिणाम अधिसूचना जापान और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल के आयात पर निश्चित शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए 08 अक्तूबर, 2010 को अंतिम परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी। निश्चित पाटनरोधी शुल्क 19 अप्रैल, 2010 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 18 अप्रैल, 2015 तक दिनांक 01 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 120/2010-सीमा शुल्क के तहत राजस्व विभाग द्वारा लगाया गया था।
- मैसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात् एचओसीएल कहा गया है), मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात् एसआई ग्रुप कहा गया है) ने दिनांक 01 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 120/2010-सीमा शुल्क तथा 18 अप्रैल, 2011 की संख्या 36/2011-सीमा शुल्क के तहत थाइलैंड और जापान से फिनोल और एसिटोन के

आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की संयुक्त निर्णायक समीक्षा शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ताओं ने जापान और थाइलैंड (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) मूल की अथवा वहां से निर्यातित उपरोक्त वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को अनुवर्ती क्षति के जारी रहने की संभावना का आरोप लगाया है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा जारी रखने और वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है।

3. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(5) के अनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिनोल (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तुएं कहा गया है) के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के लगाने को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि उक्त शुल्क समाप्त करने से पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, के लिए 09 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 5(05)-05/2015-डीजीएडी के तहत प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी। राजस्व विभाग की दिनांक 17 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 14/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 18 अप्रैल, 2016 तक शुल्क बढ़ाया गया था। जांच को पूरा करने की समय अवधि और प्राधिकारी के अंतिम परिणाम की अधिसूचना नियमावली के नियम 17 की शर्तों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा 08 जुलाई, 2016 तक बढ़ाई गई थी।

4. संबद्ध देशों के अलावा, पाटनरोधी शुल्क यूरोपीय संघ, सिंगापुर, कोरिया आरपी, चीनी तैपई, यूएसए और दक्षिण अफ्रीका के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर भी लागू है। वर्तमान समीक्षा का कार्यक्षेत्र पिछली जांचों के सभी पहलुओं को शामिल करता है और जापान एवं थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू है।

ख. प्रक्रिया

5. संबद्ध जांच के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया निम्नलिखित है:

- i. नई दिल्ली में संबद्ध देशों के दूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के बारे में सूचित किया गया था।
- ii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार, अभिज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के गैर-गोपनीय रुपांतरण की प्रतियां उपलब्ध करा दीं। आवेदन के गैर-गोपनीय रुपांतरण की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध करा दी गई थी और अन्य हितवद्ध पक्षकारों, जिन्होंने अनुरोध किया था, को भी उपलब्ध कराई गई थी।
- iii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों (जिनके नाम और पते याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) में निम्नलिखित अभिज्ञात विनिर्माताओं/निर्यातकों को सार्वजनिक सूचना की प्रतियां अग्रेषित की गई थीं और नियम 6(2) तथा 6(4) के अनुसार, पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर दिया गया था:
 - i. पीटीटी फिनोल कं. लि. (पीपीसीएल)
 - ii. चिबा फिनोल कं. लि., शिडोम
 - iii. मित्सुबिशी केमिकल्स
 - iv. मितसुई एंड कं. लि. ("एमबीके"), जापान
 - v. मैसर्स मितसुई एंड कं. (एशिया पेसिफिक) पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर
 - vi. मित्सुबिशी केमिकल कारपोरेशन ("एमसीसी")
 - vii. सुनीतोमो कारपोरेशन
 - viii. मितसुई केमिकल्स, इंक.

- iv. संबंध देशों में संबंध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्रावली के अपने उत्तर प्रस्तुत किए हैं:
1. मैसर्स पीटीटी फिनोल कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड (उत्पादक)
 2. मैसर्स मितसुई केमिकल्स, इंक., जापान (उत्पादक)
 3. मैसर्स मितसुई एंड कं. लि., जापान (निर्यातक)
 4. मैसर्स मितसुई एंड कं. (एशिया पैसिफिक) पीटीई. लि., सिंगापुर (निर्यातक)
- v. प्राधिकारी ने भारत में संबंध वस्तुओं के निम्नलिखित अभिज्ञात आयातकर्ताओं/उपभोक्ताओं (जिनके नाम और पते आवेदकों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) सार्वजनिक सूचना की प्रतियां अग्रेषित की गई थीं और नियम 6(4) के अनुसार, पत्र जारी करने की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार देने के लिए सलाह दी गई थी:
1. मैसर्स सी.जे. शाह एंड कंपनी
 2. मैसर्स हरेश कुमार एंड कं., मुंबई
 3. मैसर्स पीसीएल ऑयल एंड इंडस्ट्रीज
 4. मैसर्स कांतीलाल मणिलाल एंड कं. प्रा. लि.
 5. मैसर्स सोनकमल इंटरप्राइजेज, मुंबई
 6. मैसर्स खेतान ब्रदर्स
 7. मैसर्स शुभम डाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड
 8. मैसर्स एक्रोन इंटरप्राइजेज
 9. मैसर्स नैकनावारे केमिकल्स लिमिटेड
 10. मैसर्स पारस डाइज एंड केमिकल्स
 11. मैसर्स टोरेट फार्मास्युटिकल लिमिटेड, गुजरात
 12. मैसर्स यूनाइटेड फॉस्फोरस लि., मुंबई
 13. मैसर्स रेसिन्स एंड प्लास्टिक लि.
 14. मैसर्स कैलाश पोलिमर्स
 15. मैसर्स सेंट्रम मेटालिक्स प्रा. लि.
 16. मैसर्स बंडर लेमिनेट्स प्रा. लि.
 17. मैसर्स मेघदेव इंटरप्राइजेज
 18. मैसर्स सतगुरु इंटरनेशनल
 19. मैसर्स ब्लीच मार्केटिंग प्रा. लि.
 20. मैसर्स कारमेन इंटरनेशनल (पी) लि.
 21. मैसर्स हाई पोलिमेर लैक्स लि.

22. मैसर्स रैनबो कलर्स एंड केमिकल्स
23. मैसर्स कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रा. लि.
24. मैसर्स एनजीपी इंडस्ट्रीज लि.
25. मैसर्स फार्मसन फार्मास्युटिकल गुजरात लि.
26. मैसर्स इंडिया ग्लाइकोल लि.
27. मैसर्स सिंह प्लास्टिसीजर्स एंड रेसिन्स (आई) प्रा.
28. मैसर्स नेशनल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज लि.
29. कुंदन राइस मिल्स लि.
- vi. संबद्ध वस्तुओं के आयातकर्ताओं में से केवल एक आयातकर्ता अर्थात् मैसर्स सेंचुरी प्लाइवुड लिमिटेड ने इस मामले में किसी प्रभावली के उत्तर प्रस्तुत किए बगैर कुछ अनुरोध किए हैं।
- vii. वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2013 – सितंबर, 2014 (18 माह) थी। क्षति विश्लेषण के संबंध में रुख की जांच में 2010-11, 2011-12, 2012-13 की अवधि तथा पीओआई शामिल थी।
- viii. जांच की अवधि और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए लेन-देन-वार आयात आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अधिप्राप्त किए गए थे और इस जांच में विश्लेषण के लिए इन पर विश्वास किया गया है।
- ix. संबद्ध वस्तुओं से संबंधित निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकर्ताओं और अन्य हितवद्ध संबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने न तो प्राधिकारी को उत्तर दिया है और न ही इस जांच से संबंधित सूचना भेजी है, इस जांच में हितवद्ध पक्षकार नहीं माना गया है।
- x. प्राधिकारी नियम 6(7) के अनुसार, अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाइलें खुली रखने के रूप में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गैर-गोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराया था।
- xi. प्राधिकारी ने उत्पादन की लागत निकालने और भारत में संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षति कीमत के लिए नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाटनरोधी शुल्क पाटन मार्जिन की तुलना में घरेलू उद्योग के लिए क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xii. प्राधिकारी ने 20 जनवरी, 2016 को हुई जन सुनवाईयों में सभी हितवद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से रखने का अवसर प्रदान किया था। सुनवाईयों में उपस्थित सभी हितवद्ध पक्षकारों, जिन्होंने अपने विचार मौखिक व्यक्त किए थे, को लिखित में अनुरोध/संलग्नक प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था।
- xiii. इस जांच के दौरान हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की जांच की गई है और इस जांच परिणाम में उनका समाधान किया गया है।
- xiv. जांच के दौरान प्राधिकारी स्वयं इस बात से संतुष्ट है कि आपूर्ति की गई सूचना, जिस पर यह जांच परिणाम आधारित है, यथार्थ है। प्राधिकारी ने विचार की गई संगत सीमा तक और आवश्यकतानुसार घरेलू उद्योग

और सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के परिसरों में वहीं पर जांच की थी। क्षति से संबंधित अतिरिक्त/पूरक विवरण घरेलू उद्योग से मांगा गया था जो प्राप्त हो गया था।

- xv. गोपनीय आधार पर हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां आवश्यक था, इस प्रकार की सूचना गोपनीय मानी गई है और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकट नहीं की गई है, के गोपनीयता दावों को स्वीकार किया है। जहां संभव हुआ, गोपनीयता आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीयता आधार पर सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त गैर-गोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।
- xvi. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों के लिए 17.06.2016 को मामले के सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण जारी किया है। हितवद्ध पक्षकारों की टिप्पणियां, जहां तक वे उस सीमा तक संगत हैं, उपयुक्त स्थानों में इस जांच परिणाम में उनका समाधान कर दिया गया है।
- xvii. *** इस परिणाम में गोपनीय आधार पर हितवद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और जो नियमावली के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा मानी गई है।
- xviii. प्राधिकारी द्वारा पीओआई के लिए विनियम दर 60.76 रुपए = 1 अमेरिकी डॉलर ली गई है।

ग. संबद्ध उत्पाद और इसी प्रकार की वस्तुओं का कार्यक्षेत्र

6. दिनांक 08 अक्टूबर, 2010 की फिनोल की मूल जांच के अंतिम परिणाम में संबद्ध उत्पाद का उल्लेख निम्नानुसार किया गया था:

"विचाराधीन उत्पाद फिनोल है। यह एक ऑर्गेनिक रसायन है जिसे कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है और फिनोल फार्मैलिहाइड रसायन, लेमिनेट्स, प्लाइवुड, पार्टिकल बोर्ड्स, बिसफिनोल-ए, एलकाइल फिनोल, फार्मास्यूटिकल, डिफनाइल ऑक्साइड और डाउनस्ट्रीम केमिकल्स के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। फिनोल को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 और 27 के अंतर्गत क्रमशः उप-शीर्ष 29071110, 27079900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र के लिए किसी भी तरह से बाध्यकर नहीं है। यह एक मूलभूत ऑर्गेनिक रसायन है, दो ग्रेडों अर्थात् क्रिस्टलाइन और हाइड्रेडिड में बेचा जाता है। दो ग्रेडों का अंतर फिनोल की प्रवाह विशिष्टताओं के आधार पर किया जाता है। यह दो रूपों-खुले और थोक में बेचा और पैक किया जाता है।"

7. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा उत्पादित फिनोल भौतिक और तकनीकी विशिष्टताओं की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित फिनोल, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्दिष्टि, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का प्रशुल्क वर्गीकरण, जैसी वस्तु है। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक एवजी हैं तथा उपभोक्ता इन्हें एक-दूसरे के रूप में प्रयोग करते हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद को उप-शीर्ष 29071110 और 27079900 दोनों के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 29 और 27 (फिनोल) के अंतर्गत वर्गीकृत है।

9. उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकर्ताओं और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और इसी प्रकार की वस्तु के कार्यक्षेत्र के संबंध में कोई संबंधित अनुरोध नहीं किया गया है। यह निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण प्राधिकारी का मत है कि वर्तमान जांच में पीयूसी का कार्यक्षेत्र वही है जो मूल जांच में था।

घ. घरेलू उद्योग और स्थायी

10. जैसा कि पहले नोट किया गया है कि मैसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) तथा मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड (एसआई ग्रुप) द्वारा फिनोल और एसिटोन पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के लिए संयुक्त याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ही भारत में फिनोल और एसिटोन के उत्पादक हैं और इसलिए कुल भारतीय उत्पादन इनका है। शुरूआती चरण में याचिकाकर्ताओं द्वारा यह अनुरोध किया गया था मैसर्स एसआई ग्रुप में इन वस्तुओं का आयात कई देशों, जिसमें संबद्ध देश शामिल हैं, केवल निजी खपत के लिए शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान योजनाओं, दोनों के तहत किया था और आयातित वस्तुएं घरेलू बाजार में नहीं बेची गई थीं। आगे जांच के लंबित रहते प्राधिकारी ने शुरूआती चरण में एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग का एक घटक होने के कारण एक मात्र घरेलू उत्पादक माना है।

ष.1 विरोधी हितवद्ध पक्षकारों के विचार

11. विरोधी हितवद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों में क्षति जांच के प्रयोजन से घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से एसआई ग्रुप को बाहर करने के लिए सख्त तर्क दिए हैं और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- i. यतः आयात के कारण विगत में एसआई ग्रुप को घरेलू उद्योग से बाहर कर दिया गया है जिसमें पीओआई में 20,000 एमटी तक वर्तमान जांच में भी आयात किया गया है। इसने अनुरोध किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई कई जांचों में एसआई ग्रुप को अधिकांश मूल जांचों में आयात के कारण घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर किया गया था। इसलिए, इस पाटनरोधी जांच में एसआई ग्रुप की भागीदारी अत्यधिक असंगत है।
 - ii. यतः एसआई ग्रुप का आयात घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उत्पादन और बिक्री का अधिकांश हिस्सा है। एसआई ग्रुप ने तथाकथित पाटन के खोतों से आयात किया है और पाटन कार्यकलापों में भाग लेकर स्वयं को बचाने का प्रयास करके लाभान्वित हुआ है।
 - iii. यतः आयात निजी खपत और वाणिज्यिक बिक्री के लिए है, इसलिए असंगत है क्योंकि भारत में वाणिज्यिक बाजार में सीधे अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आयात का कोई प्रभाव है। यदि एसआई ग्रुप ने निजी खपत के लिए अधिकांश आयात का प्रयोग किया है तो वाणिज्यिक बिक्री के लिए संबद्ध उत्पाद का उत्पादन और माल-सूची निर्बाध रूप से की है, जबकि इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया है कि निजी खपत को सस्ते पाटित आयातों से प्रतिस्थापित किया गया था।
 - iv. यतः यह निर्विवाद है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू अर्थात् घरेलू उत्पादक, जो एक आयातकर्ता भी है, को शामिल करने के लिए विवेक को पूरा किया है, इसलिए इस विवेक को औचित्यपूर्ण और साम्या के आधार पर अनिवार्यतः नियंत्रित किया जाए। इसलिए घरेलू उद्योग के रूप में एसआई ग्रुप को शामिल करना औचित्य और तथ्यों की विश्लेषणात्मक जांच के आधार पर किया जाना चाहिए।
 - v. यतः विगत में प्राधिकारी द्वारा निर्णित मामलों के विपुलता में (चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बैम्बूफाइबर को छोड़कर "विस्को स्टेपल फाइबर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच-2010, चीन जनवादी गणराज्य, यूरोपियन संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एस, मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर), चीन जनवादी गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, रूस और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच-2013, इलैक्ट्रिकल इंसुलेटर-2015 आदि) कतिपय सिद्धांतों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा मुद्दे का निर्णय लिया गया है। प्राधिकारी द्वारा सामना की गई इसी प्रकार की स्थितियों में पूर्व निर्णय के प्रकाश में प्रमुख प्राचलों को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से किसी घरेलू उत्पादक को बाहर करने अथवा शामिल करते समय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए परंपरागत जांच की है और निम्नानुसार है:
- क. उत्पादन और बिक्री की तुलना में आयात की मात्रा;
- ख. आयातक गतिविधियों के विरोध स्वरूप घरेलू उत्पादन के उत्पादक द्वारा दर्शाई गई प्रतिबद्धता का दीर्घकालीन स्तर का स्वरूप;
- ग. यदि घरेलू उत्पादक को शामिल करना जांच परिणामों को विकृत करेगा तो इसे अनिवार्यतः बाहर किया जाए।
- vi. यतः अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के लिए अभिचिन्हित प्राचलों के साथ एसआई ग्रुप संबंधी उपरोक्त सूचना का मिलान करके निम्नलिखित संगत तथ्य उभरकर आएंगे।

- एसआई ग्रुप द्वारा किया गया आयात केवल उत्पादन के बड़े हिस्से के लिए नहीं किया गया है बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई विक्री भी है।
 - आंकड़ों से पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क/चालू जांच के लिए संबद्ध देशों से इसका आयात एसआई ग्रुप के कुल उत्पादन के 37% से अधिक है।
 - इसलिए, यह अविवादित है कि एसआई ग्रुप ने तथाकथित पाटन स्रोतों से आयात किया है बल्कि पाटन कार्यकलापों में भाग लेकर अपनी प्रक्रिया की रक्षा करके और तथाकथित पाटन से लाभान्वित भी हुआ है।
 - एसआई ग्रुप के वर्तमान कार्यकलाप दीर्घकालीन रूख को जारी रखने के लिए है तथा प्राधिकारी द्वारा की गई पिछली जांचों में भी मान्यता दी गई है जिससे यह स्पष्ट है कि एसआई ग्रुप का तथाकथित पाटन के स्रोतों से संबद्ध उत्पाद के आयात के लिए दीर्घकालीन प्रतिबद्धता रही है।
- vii. यतः प्राधिकारी प्रदत्त शुल्क और शुल्क मुक्त आयात में एसआई ग्रुप द्वारा किए गए आयातों और इसके प्रचालन पर उसके प्रभाव और मार्जिन तथा हितवद्ध पक्षकारों के लिए उसे उपलब्ध कराने के लिए विखण्डन एवं विश्लेषण कर सकता है ताकि इस संबंध में तर्कपूर्ण अनुरोध करने की अनुमति दी जा सके।
- viii. यतः उपरोक्त के प्रकाश में प्राधिकारी को इसके समक्ष तथ्यों और साक्ष्यों के विचार में विवेकपूर्ण तरीके से पाटनरोधी नियमावली के तहत अपने व्यापक विवेक का प्रयोग करना चाहिए और क्षति जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से एसआई ग्रुप को बाहर करना चाहिए।

ब.2 याचिकाकर्ताओं के विचार

12. अपने अनुरोधों में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि वर्तमान जांच में याचिकाकर्ताओं नामतः मैसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ही देश में संबद्ध उत्पाद के उत्पादक हैं। तथापि, मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है जबकि यह आयात संबद्ध देशों से नहीं है। इसके अतिरिक्त, ये आयात निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क छूट की योजना के तहत अथवा डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए प्रयुक्त खपत हेतु सीमा शुल्क का भुगतान करने के पश्चात किए गए हैं। कंपनी ने व्यापार प्रयोजनों के लिए आयात नहीं किया है और इसलिए, इस व्यवहार को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जाना चाहिए। आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि एसआई ग्रुप द्वारा आयात गैर-संबद्ध देशों से संबंधित है, इसलिए वे वर्तमान जांच में संबंधित नहीं हैं।

13. आगे यह तर्क दिया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी का विभिन्न एसिटोन और फिनोल मामले में मत रहा है कि आयात निजी खपत के लिए है अथवा महत्वपूर्ण रूप से वाणिज्यिक विक्री के लिए है। तथापि, उपरोक्त के होते हुए प्राधिकारी को विचार करना चाहिए कि एसआई ग्रुप घरेलू उद्योग का एक भाग नहीं हो सकता और प्राधिकारी घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से एसआई ग्रुप को बाहर कर सकता है और अकेले एचओसीएल से संबंधित आंकड़ों/सूचना के आधार पर आगे बढ़ सकता है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. प्राधिकारी ने मौजूदा नियमावली और इस मुद्दे से संबंधित विवेक के अनुसार, हितवद्ध पक्षकारों द्वारा रखे गए उपरोक्त तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति जांच के लिए घरेलू उद्योग के भाग के रूप में मानने हेतु मैसर्स एसआई ग्रुप की पात्रता के मुद्दे की जांच की है।

15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एसआई ग्रुप और एचओसीएल ने घरेलू उद्योग, शामिल देशों और दोनों उत्पादों के लिए जांच की अवधि के रूप में दोनों उत्पादों को शामिल करते हुए संयुक्त निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए संयुक्त आवेदन किया है। जांच के समय एसआई ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने निर्यात उत्पादन हेतु शुल्क छूट योजना के तहत विभिन्न देशों से प्रस्तावित पीओआई के दौरान फिनोल की कतिपय मात्रा का आयात किया था और विभिन्न देशों, जिनमें जांचाधीन देश शामिल हैं, से कुछ मात्रा का आयात डाउनस्ट्रीम उत्पादों के निजी उत्पादन हेतु लागू शुल्क का भुगतान करके किया था। कंपनी ने आगे घोषित किया है कि उन्होंने निर्यात प्रक्रमण हेतु शुल्क छूट योजनाओं के तहत एसिटोन की कुछ मात्रा का आयात किया था। यह घोषित किया गया था कि उन्होंने घरेलू बाजार में किसी आयातित वस्तु की विक्री नहीं की है। इन घोषणाओं के आधार पर एसआई ग्रुप को मामले में आगे जांच के लंबित रहते शुरूआती जांच के समय घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया था।

16. जांच के दौरान यह पाया गया है कि पीओआई के दौरान एसआई ग्रुप ने 12246.43 एमटी फिनोल का आयात किया था जिसमें से 7455.732 एमटी का आयात निर्यात उत्पादन हेतु शुल्क छूट योजनाओं के अंतर्गत किया गया था और शेष 4745.346 एमटी का आयात शुल्क का भुगतान करके किया गया था। भुगतान शुल्क आयात में से 45.35 एमटी की बिक्री घरेलू बाजार में की गई थी। आगे यह नोट किया गया है कि सभी आयात उन देशों से किया गया है जहां पाटनरोधी शुल्क लगता है और 800 एमटी थाईलैंड से आयात किया गया है जो इस मामले में जांच के अधीन देशों में से एक देश है। इस कंपनी का आयात पीओआई के दौरान फिनोल के इसके अपने उत्पादन का लगभग 23% है। इसी प्रकार, एसआई ग्रुप ने निर्यात उत्पादन हेतु शुल्क छूट योजनाओं के तहत 9924 एमटी एसिटोन का आयात किया था। आगे यह नोट किया गया है कि एसिटोन का सारा आयात उन देशों से किया गया है जहां पाटनरोधी शुल्क लगता है। तथापि, जांचाधीन देशों से कोई आयात नहीं किया गया है। एसिटोन का आयात पीओआई के दौरान इसके अपने उत्पादन का लगभग 30% है।

17. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जैसा कि, ऊपर रिकार्ड किया गया है, अपने अनुरोधों में कंपनी ने तर्क दिया था कि एसआई ग्रुप द्वारा आयात गैर-संबद्ध देशों से संबंधित है, इसलिए वे वर्तमान जांच से संबंधित नहीं हैं। आगे याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एसआई ग्रुप ने व्यापार प्रयोजनों के लिए वस्तुओं का आयात नहीं किया है और इसलिए इस व्यवहार को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जाना चाहिए। तथापि, जांच से पता चलता है कि इस कंपनी द्वारा शुल्क भुगतान के द्वारा आयातित लगभग 45 एमटी फिनोल पीओआई के दौरान बाजार में बेचा गया था। जांच से यह भी पता चलता है कि एसआई ग्रुप इन दो जांचों की पश्चात् पीओआई अवधि के दौरान फिनोल और एसिटोन, दोनों का पर्याप्त मात्राओं में आयात करता रहा। कंपनी का पिछला इतिहास दर्शाता है कि वे अपनी खपत के लिए वस्तुओं का लगातार आयात कर रहे हैं।

18. मामले की इस वास्तविक स्थिति से प्राधिकारी वर्तमान नियमावली के तहत इसके लिए उपलब्ध विवेक और घरेलू उद्योग की परिभाषा से भिन्न है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समय घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

19. वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता घरेलू उत्पादकों में से एक उत्पादक अर्थात् एसआई ग्रुप निर्यात उत्पादन के लिए मुख्य रूप से अपनी निजी खपत हेतु एसिटोन और फिनोल, दोनों के लिए आयात कर रहा है। यह तथ्य पूर्ववर्ती जांच में प्राधिकारी के समक्ष भी था और इस कंपनी को कुछ मामलों में घरेलू उद्योग में शामिल किया गया था और अन्य कुछ मामलों में इसे उन मामलों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स से बाहर किया गया था। अब यह कानून की प्रमाणित स्थिति है और अन्य जांच प्राधिकारियों में विवेकपूर्ण है तथा एडीए के अनुच्छेद 4(1) तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में उन उत्पादकों, जो पाटित उत्पादों का आयात स्वयं करते हैं, को स्वतः बाहर करने के लिए प्रावधान है, परन्तु प्राधिकारी को मामला-दर-मामला आधार पर जांच करने का अधिकार देता है। जहां इस प्रकार की स्थिति में किसी उत्पादक को शामिल करने अथवा बाहर करने की आवश्यकता हो, यह निर्धारित करने में कि घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से किसी घरेलू उत्पादक को बाहर किया जाए, प्राधिकारी सामान्यतः निम्नलिखित घटकों की जांच करता है:

- क्या आयात छूटपूट है अथवा इसके अपने उत्पादन और बिक्री की तुलना में कम है और नियमित आधार पर नहीं किया जा रहा है,
- क्या आयात कुछ स्थितियों से निजात पाने के लिए आवश्यक है अर्थात् उत्पादन मामले अथवा इसके द्वारा विनिर्मित नहीं किए जा रहे ग्रेडों को बढ़ावा देने के लिए अथवा गुणवत्ता जांच और उत्पाद विकास आदि के लिए है,
- अपनी उत्पाद रेंज को पूरा करने की जरूरत ताकि वह मानक को पूरा कर सके,
- क्या घरेलू उद्योग में परिभाषित किए जाने हेतु कोई अन्य परिवर्तनीय घरेलू उत्पाद है।

20. नियम 2(ख) के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए उपलब्ध विवेक उन स्थितियों, जहां शिकायतकर्ता उत्पादक केवल घरेलू उत्पादक है अथवा आयात उनके उत्पादन की तुलना में काफी अधिक नहीं है और/अथवा आयात उत्पाद विकास और परीक्षण आदि के लिए है, अपेक्षित सावधानी के साथ प्रयोग किया गया है। वर्तमान मामले में एसआई ग्रुप पर्याप्त मात्राओं में संबद्ध

वस्तुओं का आयात कर रहा है। यद्यपि, इसने अनुरोध किया है कि वस्तुओं की अधिकांश मात्रा निर्यात बिक्री हेतु अपने डाउनस्ट्रीम उत्पादन के लिए आयातित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आयात की कम मात्रा की घरेलू बाजार में बिक्री की जा रही है और जांच की शुरुआत के समय यह तथ्य प्राधिकारी के ध्यान में नहीं लाया गया था। यद्यपि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में देश में केवल एक अन्य घरेलू उत्पादक अर्थात् मैसर्स हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) है जिसके पास पर्याप्त उत्पादन क्षमताएं हैं। परन्तु एचओसीएल की उत्पादन सुविधाएं उत्पादन हेतु शुरू होती हैं और बंद होती हैं तथा कुछ अन्य घटकों के कारण पीओआई के दौरान केवल कुछ महीनों के लिए प्रचलित की गई थी। तथापि, घरेलू उत्पादक ने तर्क दिया है कि इस उत्पादक का उत्पादन कई घटकों से काफी प्रभावित होता रहा है। इसमें विभिन्न स्रोतों से दीर्घकाल तक पाटन शामिल है जिससे पीओआई के दौरान पर्याप्त अवधि के लिए संयंत्र बंद हो गया। इस स्थिति में यदि एसआई ग्रुप को क्षति जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के एक भाग को अनुमति नहीं दी जाती है तो क्षति का मूल्यांकन करने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई व्यवहार्य घरेलू उद्योग नहीं होगा और क्षति जांच काफी भटक जाएगी अथवा संबद्ध देशों से संभावित आयात प्रभावित अथवा आयात का औचित्यपूर्ण विश्लेषण नहीं हो सकेगा।

21. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी अपेक्षित सावधानी के साथ नियम 2(ख) के अंतर्गत इसके लिए उपलब्ध विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रवृत्त है और एसआई ग्रुप इस मामले में क्षति जांच हेतु घरेलू उद्योग के एक भाग के रूप में मानता है।

22. हितवद्ध विरोधी पक्षकारों ने अपने पञ्च: प्रकटीकरण अनुरोधों में टिप्पणी की है कि प्राधिकारी ने यह निर्धारित करने में कि किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाए, कई घटकों की जांच करके सही दिशा में कदम उठाया है। तथापि, उपरोक्त घटकों का विश्लेषण करने के बावजूद प्राधिकारी ने अपेक्षित सावधानी से नियम 2(ख) के अंतर्गत उपलब्ध अपने विवेक का प्रयोग करने का निर्णय लिया है और निर्धारित किया है कि एसआई ग्रुप घरेलू उद्योग में शामिल है क्योंकि साधारण बैट पर यदि एसआई ग्रुप को क्षति के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग का एक भाग मानने की अनुमति नहीं दी जाती है तो क्षति का मूल्यांकन करने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई व्यवहार्य घरेलू उद्योग नहीं होगा और क्षति जांच काफी भटक जाएगी अथवा आयात का औचित्यपूर्ण विश्लेषण अथवा संबद्ध देशों से आयात के संभावित प्रभाव का औचित्यपूर्ण विश्लेषण नहीं हो सकेगा। यह निश्चित रूप से एक संकटपूर्ण पूर्व उदाहरण बन जाएगा जिससे भारतीय विनिर्माता सदैव अर्हक मार्ग पाएंगे क्योंकि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के बावजूद इस प्रकार के आयात से लाभान्वित हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि यदि वे अधिकांश डाउनस्ट्रीम के लिए निर्यात करते हैं तो एसआई ग्रुप द्वारा किए गए आयात के भाग में घरेलू बाजार पर काफी प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त, एसआई ग्रुप इन आयातों से स्पष्ट रूप से लाभान्वित हुआ है क्योंकि यह निर्यात बाजार में अपने डाउनस्ट्रीम उत्पाद के प्रतिस्पर्द्धी मूल्य के लिए सक्षम है।

23. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विरोधी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जांच की गई है और मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में इस मामले में क्षति जांच के लिए घरेलू उद्योग के भाग के रूप में एसआई ग्रुप को रखना आवश्यक पाया गया है।

ड. इस जांच के लिए हितवद्ध पक्षकार

24. याचिकाकर्ताओं के अलावा उन उत्तर देने वाले निर्यातकों और आयातकर्ताओं, जिन्होंने उपरोक्त पैरा 5(iv) और (vi) में सूचीबद्ध अनुसार इस जांच में हितवद्ध पक्षकार के रूप में अपने को ज्ञात बताता है और उत्तर देने वाले देशों की सरकारों को इस जांच में हितवद्ध पक्षकार माना गया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 गोपनीयता

25. विरोधी हितवद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों में तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने क्षति अवधि फिनोल की अतिरिक्त गोपनीयता और उत्पादन आंकड़ों का दावा किया है और पीओआई उपलब्ध नहीं कराई गई है जबकि याचिका में एसिटोन के लिए उपलब्ध कराई गई है। यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को निर्यात कीमतों के समायोजनों के लिए आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है और फॉर्मेट क, ख, ग-1, ग-2, घ और ङ में लागत सूचना के लिए इंडेक्स रेंज उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा कम क्रम कीमत मार्जिन, नियोजित पूँजी और गैर-क्षति कीमत सार रूप में अथवा इंडेक्स रेंज याचिका में प्रकट नहीं की गई है।

26. गोपनीयता मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के सभी गोपनीयता दावे कानूनी प्रावधानों, डीजीएडी द्वारा जारी किए गए व्यापार नोटिस और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा पालन की जा रही प्रक्रिया के

अनुसार है। आगे यह अनुरोध किया गया है कि हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर अत्यधिक गोपनीय है और औचित्यपूर्ण अनुरोध करने के लिए घरेलू उद्योग को रोकते हैं।

27. गोपनीयता के संबंध में हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सम्भव और व्यावहारिक सीमा तक सूचना प्रस्तुत करने वाले विभिन्न पक्षकारों के गोपनीयता दावों की जांच की गई है और गोपनीयता दावे पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रकृति के आधार पर स्वीकार किए गए हैं। जहां तक निर्यातकों के अनुरोधों का संबंध है, उल्लेखनीय है कि निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना उसे उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के लिए कारोबार संवेदनशील नहीं है और सार्वजनिक फाइल में रख दी गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विरोधी पक्षकारों के गोपनीयता दावों के संबंध में सभी पक्षकारों की आपत्तियों का निपटान कर दिया गया है।

च.2 अन्य मुद्दे

28. विरोधी हितवद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर निर्णायक समीक्षा के लिए याचिका में उस समय तक कमी है जो सम्भावना का पर्याप्त समाधान नहीं करता है और अपने दावों को परिपुष्टि के लिए किसी साक्ष्य के बिना आधारहीन आरोप लगाता है। वास्तव में बने रहने की संभावना के दावों के संबंध में याचिकाकर्ता अपने आपको विरोधाभासी प्रतीत लगते हैं। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने निष्पादन में कोई सुधार नहीं दर्शाया है। उसी पैरा में याचिकाकर्ताओं ने तब कहा था कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि पाटन निम्न स्तर पर जारी है। इस प्रकार के अस्पष्ट विवरणों का अभिप्राय हितवद्ध पक्षकारों और निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुमराह करना है। इसलिए याचिका को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

29. जहां तक जापान से संबद्ध वस्तुओं के आयात का संबंध है, याचिकाकर्ताओं आगे अपनी याचिका के संबंध में अपने को एकदम से प्रतिकूल पाते हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि जांच की अवधि और पिछले वर्ष जापान से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है।

30. यह अनुरोध किया गया है कि प्राधिकारी ने कई जांचों में इस प्रकार तथ्यात्मक परिदृश्य की जांच की जिसमें हाल ही के वर्षों में संबद्ध देशों से इस समय कोई आयात नहीं हुआ है और इस प्रकार के मामलों में शुल्क को प्रतिसंहरण करती है। इसलिए तथ्यों कि (i) जापान से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है (ii) पीओआई के दौरान एसआई ग्रुप के एक प्रमुख आयातक होने के कारण संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का कोई कारण नहीं है।

31. अपने अनुरोधों में निर्यातकों ने भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अन्तर्विहित रूप से अदक्ष हैं और उनकी प्रचालनात्मक कमजोरी बाधाओं के कारण क्षति हुई है और एक दशक से अधिक के लिए पाटनरोधी उपायों पर बार-बार विश्वास करने का सहारा लिया। यह तर्क दिया गया है कि 1987 में इसके संयंत्र की स्थापना के बाद से एचओसीएल अपनी उत्पाद सुविधा अथवा प्रक्रिया में कोई सुधार करने में विफल रहा है। यद्यपि 1999 के बाद देश में मांग लगभग 200 प्रतिशत बढ़ गई है। 2005 से एचओसीएल को एक रूग्ण कंपनी वर्गीकृत किया गया है और एचओसीएल के अपरिष्कृत फिनोल विनिर्माण संयंत्र की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल ही में गिरावट के कारण बंद कर दिया गया है और एचओसीएल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि संयंत्र कच्चे माल की कमी के कारण बंद किया गया है जिसका संबद्ध वस्तुओं के तथाकथित पाटन से कोई संबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, कार्यचालन पूंजी की अत्यधिक कमी के कारण उत्पादन बंद करना पड़ा।

32. अपने संक्षिप्त अनुरोधों में उपरोक्त मैसर्स सेंचुरी प्लाईवुड बोर्ड लिमिटेड के अलावा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- कि वे फिनोल के प्रमुख प्रयोक्ताओं में से एक है जो एचओसीएल के अनुरोध पर लम्बे समय के लिए पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन है।
- कि एचओसीएल ने अगस्त, 2015 से अपना फिनोल संयंत्र बंद कर दिया है और इसके बाद एचओसीएल फिनोल की आपूर्ति नहीं कर सका। पहले भी वे मध्यवर्ती रूप से काम कर रहे हैं।
- कि संयंत्र बंद करने के पश्चात एचओसीएल ने टोल संविदा आधार पर संयंत्र चलाने के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु निविदाएं जारी की हैं। तथापि, संयंत्र और मशीनरी की हालत को ध्यान में रखते हुए निविदा में भाग लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है।
- दूसरी तरफ संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ता पर आवश्यक रूप से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का भार है। इसलिए शुल्क जारी रखने का कोई कारण नहीं है।
- अनौचित्यपूर्ण लेवी और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण उपभोक्ताओं और अंतिम प्रयोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ का कारण है और अर्थव्यवस्था की मंदी में योगदान कर रहा है।

33. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का अभिप्राय और प्रयोजन यह है कि घरेलू उद्योग को उचित कीमतों पर अपनी सामग्रियों की विक्री करने के लिए वधित उचित बाजार अवसर प्राप्त होते हैं। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाने से उचित बाजार अवसर प्राप्त नहीं करता। तथापि, पाटनरोधी शुल्क समाप्ति से शुल्क की पुनरावृत्ति जारी रहेगी और उसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

34. अपने पक्ष: प्रकटीकरण अनुरोधों में विरोधी हितवद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि वर्तमान जांच के गुण-दोषों का पर्याप्त विश्लेषण केवल तभी किया जा सकता है जबकि एडी शुल्क के इतिहास पर यथाअपेक्षित विचार किया जाए। प्राधिकारी ने प्रकटीकरण विवरण में इस तथ्य को नोट किया है। यह तर्क दिया गया है कि इसकी अपनी अदक्षता प्रतिरोध के लिए दशक के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा बार-बार निर्भर रहा है और घरेलू बाजार से सभी प्रतिस्पर्द्धा को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने का प्रयास किया है।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद की पाटनरोधी जांच का लम्बा इतिहास रहा है और 2002 के बाद विभिन्न देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर शुल्क लगाया गया है। संबद्ध देशों के अलावा शुल्क चीनी तैपई, यूएसए, ई.यू., कोरिया आरपी, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर से आयातों के लिए इस समय लागू है।

36. हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी शुल्क के लिए बार-बार संरक्षण की अनुमति मांगते हैं जबकि अन्तर्विहित रूप से अदक्ष हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी निर्णायक समीक्षा जांच में मूल जांच के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए प्राधिकारी की यह निरन्तर प्रक्रिया है। इसमें शुल्क को समाप्त करने पर भी पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है। तदनुसार, हितवद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की उस सीमा तक जहां तब के संगत है और साक्ष्यों पर परिपुष्ट है, विधिवत रूप से जांच की गई है।

37. पाटन और क्षति के संबंध में हितवद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए अथवा सभी मुद्दों की उस सीमा तक संगत है और साक्ष्य द्वारा परिपुष्ट है, इस जांच परिणाम में संबंधित वर्गों का समाधान किया गया है।

ज. वर्तमान पाटन की पद्धति और निर्धारण

ज.1 कानूनी याचिकाएं

38. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा:

परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।

परन्तु यदि समीक्षा पांच वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व शुरू की गई है, इस प्रकार की समाप्ति से पूर्व किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे हैं, आगे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए इस प्रकार की समीक्षा के परिणाम के लंबित रहते पाटनरोधी शुल्क जारी रहेगा।

39. तदनुसार, किसी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को निम्नलिखित जांच करनी होती है:

- क्या पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद पाटन जारी रहता है और यदि हां तो क्या इसके जारी रहने की संभावना है।
- उस मामले में जहां पाटन जारी नहीं रहता तो क्या पाटनरोधी शुल्क के प्रतिसंहरण की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होगी।
- क्या घरेलू उद्योग को काफी क्षति होगी पहेगी और यदि हां तो क्या यदि शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होते रहने की संभावना है।
- उन मामलों में जहां घरेलू उद्योग ने निरंतर क्षति वहन नहीं की है, क्या पाटनरोधी शुल्क के प्रतिसंहरण की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की सम्भावना है।

40. इसलिए, प्राधिकारी पहले यह जांच करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रहता है और क्या जांच किए जाने से यदि शुल्क का प्रतिसंहरण किया जाता है तो पाटन जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है और क्या इस प्रकार के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर्याप्त क्षति वहन करता रहेगा और इस प्रकार की स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ख.2 पाटन के जारी रहने की जांच: सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाइलैंड और जापान के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

1. मैसर्स पीटीटी फिनोल कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड (उत्पादक)
2. मैसर्स मितसुई केमिकल्स, इंक., जापान (उत्पादक)
3. मैसर्स मितसुई एंड कं. लि., जापान (निर्यातक)
4. मैसर्स मितसुई एंड कं. (एशिया पसिफिक) पीटीई. लि., सिंगापुर (निर्यातक)

42. इन दो देशों से संबद्ध वस्तुओं के वर्तमान पाटन और पाटन के जारी रहने की संभावना अथवा पुनरावृत्ति के लिए सहयोगी निर्यातकों द्वारा दायर की गई सूचना के आधार पर जांच की गई है तथा घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सूचना निम्नानुसार है:

(क) थाइलैंड

43. डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों के अनुसार पीओआई के दौरान थाइलैंड से 34,308 एमटी फिनोल का आयात किया गया था। थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं के एक उत्पादक मैसर्स पीटीटी फिनोल कंपनी लिमिटेड, थाइलैंड (पीपीसीएल) ने इस मामले में अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। इस निर्यातक के जांच किए गए आंकड़ों के अनुसार उन्होंने इस अवधि के दौरान भारत को (***) एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था। निर्यात और आयात के बीच समय को ध्यान में रखते हुए आंकड़े अनुरूप प्रतीत होते हैं।

44. पीओआई के दौरान पीपीसीएल ने भारत को सीधे तथा असंबद्ध निर्यातकों अर्थात् मैसर्स मितसुई एंड कं. लि., जापान और मैसर्स मितसुई एंड कं. (एशिया पसिफिक) पीटीई. लि., सिंगापुर के जरिए निर्यात किया था। इन असंबद्ध निर्यातकों ने भी अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। दायर किए गए उत्तरों की उसी स्थान पर जांच की गई थी। तदनुसार, उत्पादक और निर्यातकों के जांचे गए आंकड़ों के आधार पर नीचे दिए अनुसार सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है।

सामान्य मूल्य

45. पीओआई के दौरान पीपीसीएल ने असंबद्ध ग्राहकों के लिए घरेलू बाजार में (***) किग्रा. संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की। इसमें से अधिकांश विभिन्न भुगतान शर्तों के साथ सुपुर्दगी आधार पर कुछ लेन-देन के साथ कारखाना बाह्य आधार पर थी। यह नोट किया गया है कि संपूर्ण पीओआई के दौरान घरेलू बिक्री हुई थी, इसलिए निर्यात बिक्री केवल पीओआई के कुछ महीनों में हुई थी। वैश्विक बाजार में आधारभूत कच्ची सामग्रियों अर्थात् बेजिन और प्रोपेलीन की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव के कारण उत्पादक ने मासिक आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमतें निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया है और फिनोल की माह-वार लागत शीट उपलब्ध कराई है। तदनुसार, माह-वार घरेलू बिक्री साधारण व्यापार परीक्षण के अध्यक्षीन थी और मासिक सामान्य मूल्य नीचे तालिका में दिए गए पाटन मार्जिन के अनुसार अंतर्देशीय माल-भाड़ा, संभाल व्यय तथा ऋण लागत, जहां लागू हों, के लिए व्यय हेतु घरेलू बिक्री कीमत को समायोजित करने के पश्चात् नीचे दिए अनुसार निर्धारित किया गया है।

निर्यात कीमत

46. पीओआई के दौरान पीपीसीएल ने असंबद्ध व्यापारियों और अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए लेन-देन हेतु (***) किग्रा. की तुलना में भारत को (***) किग्रा. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया। इसमें से (***) किग्रा. व्यापार कंपनी मितसुई एंड कं., जापान के जरिए निर्यात किया गया था, जिसने अपनी संबंधित कंपनी मैसर्स मितसुई एंड कं. (एशिया पसिफिक) पीटीई. लि., सिंगापुर के जरिए वस्तुओं का निर्यात किया। इन दोनों कंपनियों ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं। केवल थोड़ी मात्रा (केवल एक लेन-देन) में हांगकांग में दूसरी व्यापार कंपनी के जरिए बिक्री की गई थी। शेष मात्रा भारत में ग्राहकों को सीधे बेची गई।

47. जहां तक मैसर्स मितसुई एंड कं. लिमिटेड (एमबीके) के जरिए निर्यात का संबंध है, उल्लेखनीय है कि एमबीके पीपीसीएल से वस्तुएं खरीदता है और अपनी संबद्ध कंपनी मैसर्स मितसुई एंड कं. (एशिया पसिफिक) सिंगापुर ("एमएपी") को बिक्री करता है जो विभिन्न देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, को वस्तुओं की बिक्री करता है। पीओआई के दौरान एमबीके ने एमएपी के जरिए (***) लेन-देन के लिए भारत को (***) संबद्ध वस्तुओं (थाई मूल की) का निर्यात किया गया है। सभी लेन-देन 90 दिनों की टीटी अवधि के साथ एफओबी/सीएफआर अवधि तक एमएपी के लिए बीजक किए गए तथा एमएपी ने भारत में स्वतंत्र अंतिम प्रयोक्ताओं को वस्तुओं की बिक्री की है। पीपीसीएल का सीधा निर्यात विभिन्न ऋण शर्तों सहित एलसी के लिए कारखाना बाह्य/एफओबी/सीएफआर शर्तों पर करता था।

48. फिनोल पहले घरेलू और निर्यात, दोनों के लिए थोक में वितरण हेतु थाई टैंक टर्मिनल को सुपुर्द किया गया था। कंपनी नियत फीस का भुगतान करती है और थाई टैंक टर्मिनल को थ्रो-पुट की फीस देती है। तदनुसार, पीपीसीएल ने संभाल व्यय का दावा किया है जिसमें भंडारण और थ्रो-पुट व्यय शामिल है। इसके सीधे निर्यात के साथ-साथ व्यापार कंपनियों के जरिए निर्यात के लिए कंपनी की निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमतों, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़े, संभाल व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार और कमीशन, जहां लागू हो, के लिए अपेक्षित समायोजन करने के पश्चात निर्धारित किया गया है। निर्यात थोक में है और कोई पैकिंग व्यय शामिल नहीं है। तदनुसार, नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिए अनुसार माह-वार निवल कारखाना बाह्य निर्यात के लिए निकाली गई है।

पाटन मार्जिन: पीपीसीएल-एमबीके-एमएपी

49. कारखाना बाह्य स्तर पर निर्धारित माह-वार सामान्य मूल्य की तुलना नीचे दिए अनुसार पाटन मार्जिन प्राप्त करने के लिए माह-वार निवल कारखाना बाह्य निर्यात कीमत से की गई है:

रॉ लेबल	मात्रा का योग किग्रा. में	एनबी यूएस डॉलर/किग्रा	ईपी यूएस डॉलर/किग्रा	डीएम यूएस डॉलर/किग्रा	डीएम %
उपभोक्ता	***			***	0-5%
अप्रैल-13	***	***	***	***	
मई-13	***	***	***	***	
अगस्त-13	***	***	***	***	
नवंबर-13	***	***	***	***	
फरवरी-14	***	***	***	***	
जून-14	***	***	***	***	
अगस्त-14	***	***	***	***	
सितंबर-14	***	***	***	***	
व्यवसायी	***	***	***	***	0-5%
अप्रैल-13	***	***	***	***	
मई-13	***	***	***	***	
जुलाई-13	***	***	***	***	
अगस्त-13	***	***	***	***	
जनवरी-14	***	***	***	***	
फरवरी-14	***	***	***	***	
अप्रैल-14	***	***	***	***	

मई-14	***	***	***	***	
जून-14	***	***	***	***	
जुलाई-14	***	***	***	***	
अगस्त-14	***	***	***	***	
सितंबर-14	***	***	***	***	
सकल योग	***	***	***	***	0-5%

50. अपनी पश्चः प्रकटीकरण टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चूंकि हांगकांग में व्यापारी, जिसने पीओआई के दौरान एकमात्र लेन-देन किया है, निर्यात का चैनल पूरा नहीं है और इसलिए पीटीटी फिनोल को व्यक्तिगत मानने से मना किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हांगकांग व्यापार कंपनी के लिए पीटीटी का निर्यात अकेला लेन-देन था जो भारत को कुल निर्यात के 5% से भी कम है और इसलिए किसी महत्वपूर्ण आंकड़े के अभाव में निर्धारण प्रभावित नहीं हुआ है।

थाइलैंड से सभी अन्य निर्यातक

51. पीओआई के दौरान थाइलैंड से सम्पूर्ण निर्यात पीपीसीएल द्वारा किए गए निर्यात के लिए थाइलैंड में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। इसलिए थाइलैंड में अन्य उत्पादकों और निर्यातकों के लिए शेप पाटन मार्जिन का निर्धारण निष्फल है और इसलिए आगे नहीं लाया गया है।

(ब) जापान

52. विश्वसनीय डीजीसीआईएंडएस आंकड़े दर्शाते हैं कि पीओआई के दौरान जापान से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है। 2012-13 के दौरान केवल 48 एमटी की बहुत कम मात्रा का आयात किया गया था और उसके पश्चात कोई आयात नहीं किया गया है। संबद्ध वस्तुओं को एक अग्रणी उत्पादक मैसर्स मितसुई केमिकल्स इंक., जापान ने प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है और अनुरोध किया है कि उन्होंने पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। इसलिए जापान के संबंध में कोई पाटन मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है।

53. उपरोक्त जांच दर्शाती है कि पीओआई के दौरान थाइलैंड से आयातित संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन डी-मिनिमस स्तर से मामूली अधिक था और उक्त अवधि के दौरान जापान से कोई पाटन नहीं हुआ था।

ज. पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

ज.1 विरोधी हितवद्ध पक्षकारों के मत

54. अपने अनुरोधों में विरोधी हितवद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि:

- याचिकाकर्ताओं ने अस्पष्ट और अप्रमाणित पाटन मार्जिन की गणना की है।
- याचिकाकर्ताओं ने निर्यातानुसूची प्रमाणित करने के लिए न तो कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया है बल्कि इस संबंध में तीसरे देश के आंकड़ों के स्रोत और साक्ष्य देने में विफल रहे हैं। उन्हें यह प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए।
- कीमत आकर्षण का तर्क विरोधाभासी है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के आंकड़े सुझाव देते हैं कि भारत के लिए वर्तमान निर्यात कीमत लागत की वसूली हेतु अनुमति नहीं देते। याचिकाकर्ताओं का तर्क उत्पादक की संतुलन अवधारणा के विरोधाभासी है। वे आकर्षक होने के लिए लागत से कम पर बिक्री करने का दिखावा करते हैं।
- पीओआई में कम क्रय कीमत लगातार बनी रही है। क्षति की सीमा और लाभप्रदता में अभी अत्यधिक अंतर देखे गए हैं। घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई क्षति का कम क्रय कीमत से कोई संबंध नहीं है।

ज.2 घरेलू उद्योग के मत

55. अपने अनुरोधों में, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि:

- i. थाइलैंड के मामले में पाटन जारी है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में संभावना बनी रहने के संबंध में निर्धारण की अनुमति देने के लिए थाइलैंड के मामले में आयात की मात्रा काफी अधिक है।
- ii. जापान के मामले में वर्तमान पीओआई के दौरान कोई आयात नहीं हुआ है। तथापि, पाटित कीमतों पर तीसरे देशों के लिए पर्याप्त निर्यात की उपस्थिति पाटन और क्षति की संभावना को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
- iii. तीसरे देशों को जापान से पर्याप्त निर्यात काफी क्षति मार्जिन दर्शाता है। थाइलैंड से भी तीसरे देशों में काफी पाटन हुआ है। इसलिए, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में पाटन हो रहे इन तीसरे देश के आयातों की अच्छी संभावना है।
- iv. पिछले जांचों और वर्तमान याचिका में निर्धारित पाटन मार्जिन पर्याप्त हैं और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना और परिणामी क्षति स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
- v. वे कीमतें जिन पर संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं, घरेलू बाजार में बिक्री की जा रही वस्तुओं की कीमतों से काफी कम हैं।
- vi. काफी कम क्रय कीमत है और यदि शुल्क का प्रतिसंहरण किया जाता है तो इसके बढ़ने की संभावना है। कीमत, जिस पर जापानी निर्यातकों ने पीओआई में तीसरे देशों के लिए संबद्ध उत्पाद का निर्यात किया है, को ध्यान में रखते हुए जापानी निर्यातकों द्वारा पर्याप्त कम क्रय कीमत की संभावना है।
- vii. बने रहने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के विवरणों में कोई विरोधाभास नहीं है। संबद्ध उत्पाद का पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, वर्तमान संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को क्षति, अन्य पाटन स्रोतों से घरेलू उद्योग को क्षति, पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में वर्तमान संबद्ध देशों से घरेलू उद्योग को क्षति, सभी विभिन्न प्राचलों है और तदनुसार, इन पर अनिवार्यतः विचार किया जाना चाहिए।
- viii. अतिरिक्त क्षमता संभावना को निर्धारित करने का एक सिद्ध मापदंड है, यह घरेलू उद्योग को क्षति की उच्च संभावना को दर्शाने के लिए पर्याप्त है।
- ix. किसी देश में अतिरिक्त क्षमता से स्वयं के देश में अनेक समस्याएं हो सकती हैं जैसे उत्पाद की गिरती हुई कीमतें, लाभप्रदता में कमी, कापरेट क्षेत्र पर संकट और वित्तीय क्षेत्र पर संकट जो उत्पादक को निपटान योग्य कीमतों पर देश से बाहर के स्थानों की तलाश करने को विवश कर सकती हैं। नागरिकों की क्रय क्षमता उसी दर से नहीं बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में चूंकि मांग पहले ही अधिक है, निवेश नियंत्रित हैं क्योंकि ऐसी स्थिति में निवेशों से लाभ के बजाय हानि ही होगी। क्षमता की अधिकता पाटनरोधी जाँच में संभावना के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण संकेतक होती है।
- x. यह आवश्यक नहीं है कि कीमत कटीती में वृद्धि घाटों में वृद्धि के साथ होती है। ये दोनों अलग-अलग मापदंड हैं।

56. अपने-अपने प्रकटन के बाद के अनुरोधों में घरेलू उद्योग और प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों ने पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने के संबंध में अपनी स्थितियों को दोहराया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

57. पूर्ववर्ती खंड में यह नोट किया गया कि जाँच अवधि के दौरान जापान से कोई पाटित आयात नहीं हुए थे। थाइलैंड से पाटन का मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से मामूली अधिक है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, इस समीक्षा में इस बात की जाँच

किया जाना अपेक्षित है कि क्या यदि शुल्क को हटाया जाता है तो पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस संबंध में प्राधिकारी ने संबंधित देशों में प्रमुख उत्पादकों के कीमत संबंधी व्यवहार और क्षमताओं की जाँच की है।

58. जहाँ तक थाइलैंड का संबंध है, पीपीसीएल थाइलैंड में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है जिसकी क्षमता लगभग (***) केटी प्रति वर्ष है जिसपर वे 100 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग पर प्रचालन करते हैं। पीपीसीएल द्वारा प्रस्तुत आकड़ों से पता चलता है कि यद्यपि क्षति अवधि के दौरान उनकी घरेलू बिक्री और आवद्ध अंतरण बढ़े हैं तथापि निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखी है। प्राधिकारी को यह बताया गया है कि पीपीसीएल घरेलू बाजार और तीसरे देशों से प्रमुख मांग को पूरा करने के लिए अपनी फेनोल की क्षमता को दुगुना करने के लिए निकट भविष्य में लगभग (***) केटीए की क्षमता वृद्धि करने पर विचार कर रहा है। थाइलैंड में फेनोल की वर्तमान मांग लगभग 330,000 एमटी प्रति वर्ष है जो मुख्यतः बीपीए के उत्पादन हेतु है। थाइलैंड में बीपीए के केवल दो उत्पादक हैं अर्थात् पीपीसीएल और बायर थाइ कंपनी लिमिटेड जो फेनोल की 90 प्रतिशत से अधिक मांग की खपत करते हैं। पीपीसीएल से फेनोल की निर्यात मात्रा में पीपीसीएल द्वारा उसके अपने डीआईएस-फेनानेल-ए (बीपीए) उत्पादन, जिसका मुख्यतः चीन को निर्यात किया जाता है, के लिए फेनोल की आवद्ध रूप से खपत शुरू किए जाने के बाद काफी गिरावट आई है। नया संयंत्र इस बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए है। बायर थाइ की खपत के साथ थाइलैंड में फेनोल की कुल घरेलू खपत लगभग (***) केटीए होगी और केवल लगभग (***) केटीए निर्यातों के लिए उपलब्ध होगा। तथापि, पीपीसीएल ने यह बताया है कि उनके पास अपनी अतिरिक्त क्षमता के लिए कोरिया, ताइवान, चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों के लिए पहले से ही काफी प्रतिबद्ध/संविदागत मात्राएं हैं। अतः ऐसे लगता है कि पीपीसीएल के पास निकट भविष्य में भारत को निर्यात की मात्रा अधिक बढ़ाने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता नहीं होगी।

59. जाँच अवधि के दौरान पीपीसीएल की कीमत की प्रवृत्ति दर्शाती है कि घरेलू बाजार, भारत और तीसरे देशों को निर्यात की कीमतों में बहुत कम अंतर है। पूर्ववर्ती खंड में निर्धारित पाटन का वास्तविक मार्जिन न्यूनतम सीमा से मामूली रूप से अधिक है। इसलिए, यह तर्क कि थाइलैंड से तीसरे देश को निर्यात पाटन कीमतों पर हुए हैं और इसलिए यदि शुल्क हटाया जाता है तो भारत को भारत को भारी पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है, वैध प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में जाँच अवधि के बाद (अक्टूबर 2014-मार्च 2015) के आकड़ों की जाँच की गई है और आकड़ों से पता चलता है कि कुल आयात, तथा थाइलैंड से आयातों में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि एचओसीएल ने पूर्ण रूप से उत्पादन बंद कर दिया और लगभग 40,000 एमटी के अतिरिक्त अंतर को बड़े हुए आयातों के जरिए पूरा करना पड़ा। कीमत के क्षेत्र में, सभी देशों से कीमतों में 2015 की पहली तिमाही से भारी कमी इसलिए देखी गई क्योंकि अपरिष्कृत कीमतों की स्थिति ऐसी थी। अतः ऐसा लगता है कि यदि शुल्क हटाया भी जाता है तो थाइलैंड से आयात वर्तमान स्तर पर जारी रहेंगे। चूंकि थाइलैंड की कीमतों वैश्विक रूझानों के अनुसार है, इसलिए इस उत्पादक द्वारा कीमतों में अन्य वैश्विक उत्पादकों की तुलना में प्रमुख कटौती आसन्नवर्ती प्रतीत नहीं होती है।

60. जापान के संबंध में, पीओआई और पीओआई के बाद की अवधि के दौरान इस देश से कोई आयात नहीं हुआ है। क्षति जाँच अवधि के दौरान 2011-12 में कुछ आयात हुए और 2012-13 में 45 एमटी की काफी कम मात्रा का आयात हुआ। हितवद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार जापान में फेनोल का कुल उत्पादन मोटे तौर पर 600 केटी/प्रतिवर्ष की वार्षिक मांग की तुलना में मोटे तौर पर 775 केटी/प्रतिवर्ष है। मितसुई कैमिकल्स जो लगभग (***) केटी के वार्षिक उत्पादन के साथ जापान में एक प्रमुख उत्पादक हैं ने अपने उत्तर में बताया है कि वह पहले ही लगभग (***) केटी प्रतिवर्ष का उत्पादन कर रहे हैं इस प्रकार कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होने का पता चलता है। उसकी वार्षिक बिक्री लगभग (***) केटी है और शेष आवद्ध खपत है। एमसीआई के अनुरोध के अनुसार उसकी बिक्री का (***) प्रतिशत आवद्ध खपत और घरेलू बिक्री के लिए होता है और शेष निर्यात के लिए होता है। उसके निर्यातों के लगभग (***) केटी प्रतिवर्ष की भारी कमी आई है। अपने उत्तर में कंपनी ने बताया है कि उसने डेडमिस्तु कोसान के साथ अपने संयुक्त उद्यम को सितम्बर 2014 में बंद कर दिया है जिससे उसकी क्षमता में और कमी होने का पता चलता है।

61. एमसीआई द्वारा दर्शाए गए कीमत स्तर से पता चलता है कि सकल स्तरीय घरेलू कीमत निर्यात कीमत की तुलना में अधिक हैं यद्यपि निर्यात घरेलू बिक्री की तुलना में काफी कम हैं। पीओआई के दौरान भारत को कोई निर्यात नहीं किया गया क्योंकि जापान पर भारी पाटनरोधी शुल्क लागू था। पीओआई के बाद भी जापान से कोई आयात नहीं हुए हैं। अतः यदि शुल्क हटाया जाता है तो पाटन कीमतों पर जापान से भारतीय बाजार में आयातों की कुछ मात्रा के प्रवेश करने की संभावना है। परंतु काफी अधिक आयातों की संभावना उस देश में मांग पूर्ति की स्थिति को देखते हुए कम प्रतीत होती है।

62. उक्त सभी बातों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का मत है कि यद्यपि थाइलैंड से आयात वर्तमान स्तर पर जारी रह सकते हैं और यदि शुल्क हटाया जाता है तो कुछ आयात हो सकते हैं, तथापि यदि शुल्क को हटाया जाता है तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के भारी पाटन की पुनरावृत्ति होने की कोई निकट संभावना नहीं है।

ख. क्षति और कारणात्मक संबंध के निर्धारण की पद्धति

63. जैसा पहले नोट किया गया है, किसी निर्णायक समीक्षा जाँच में क्षति जाँच के लिए प्राधिकारी के लिए इस बात की जाँच करना अपेक्षित है:

- क्या घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी है और यदि हाँ तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की संभावना है।
- ऐसे मामलों में जहाँ घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है उनमें क्या यदि पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

64. अतः प्राधिकारी ने संबद्ध देशों पर शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जाँच की कार्यवाही करने से पहले इस बात की जाँच की है कि क्या घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन आयातों के कारण वास्तविक क्षति होना जारी है। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की जाँच पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध II के अनुसार की गई है।

ग. क्षति और कारणात्मक संबंध का उदाहरण

ग. 1 प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों के अनुरोध

65. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. याचिकाकर्ता के अनुरोधों में विरोधाभास है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में कोई सुधार नहीं हुआ है और इसी के साथ घरेलू उद्योग यह दावा करता है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें पाटन निम्न स्तर पर जारी रहा है और घरेलू उद्योग को कम पाटन के कारण क्षति नहीं हुई है परंतु यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- ii. बाजार आसूचना के अनुसार यह जाना जाता है कि संबद्ध वस्तु के आयातों का एक बड़ा हिस्सा क्षति अवधि के दौरान और जाँच अवधि के दौरान अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत किया गया है। उक्त स्कीम के अंतर्गत अपने तैयारउत्पादों को बेचने का इच्छुक कोई घरेलू उत्पादक उक्त अग्रिम लाइसेंस स्कीम के अंतर्गत अपनी कच्ची सामग्री का आयात कर सकता है। ऐसी किसी स्कीम का लाभ यह होगा कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए किसी भी आयात को किसी पाटनरोधी और रक्षोपाय शुल्क से छूट प्राप्त होगी। एसआई ग्रुपजो इस मामले में एक आवेदक है, ने अग्रिम लाइसेंस के अधीन संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का आयात किया है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को एसआई ग्रुप के आयातों को शुल्क प्रदत्त और शुल्क मुक्त आयातों के रूप में अलग-अलग करना चाहिए और उसे हितबद्ध पक्षोंको उपलब्ध कराना चाहिए।
- iii. *वेटकेयन आर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेस्टेट, चेन्नई, 2011 (269) ई.एल.टी. 444 (मद्रास), और थार्ड एक्रिलिक फाइबर कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2010 (253)ई.एल.टी. 564 (टीआरआई – दिल्ली)* मामलों में निर्णय का उल्लेख करते हुए प्रतिवादी हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि अग्रिम लाइसेंस के तहत किए गए आयातों की पहचान की जाए और उन्हें क्षति और पाटन की जाँच करने के लिए विचारित आयात मात्रा से बाहर रखा जाए।
- iv. कि एचओसीएल द्वारा उठाई गई कोई क्षति उसकी स्वयं की कमियों, प्रचालनात्मक खामियों और अन्य अड़चनों से हुई है और वह एक दशक से पाटनरोधी कानून का संरक्षण मांगता रहा है जो अब 2002से अनेक जाँचों को देखते हुए स्पष्ट है।
- v. कि 1999 में एक रक्षोपाय जाँच में एचओसीएल ने रक्षोपाय शुल्क के बदले एक समायोजन योजना प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने क्षमता को बढ़ाने और लागत को कम करने के लिए कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण योजनाएं दी थीं क्योंकि उन्होंने तब स्वीकार किया था कि उनके द्वारा अभिज्ञात किया गया एक कारण पैमाने की किफायत का अभाव है। उस स्वीकृत तथ्य और समायोजन योजना के बावजूद एचओसीएल की क्षमता 1999 के उसी स्तर पर बनी हुई है।

- vi. कि वर्तमान याचिका में एचओसीएल ने स्वीकार किया है कि लम्बे समय तक बंदी कच्ची सामग्री की कमी और अन्य समस्याओं जिनका संबद्ध वस्तु के कथित पाटन से कोई सहसंबंध नहीं है का परिणाम है। संबंधित मंत्रालय और विभिन्न पाटनरोधी शुल्कों से मदद के बावजूद एचओसीएल को एसआईसीए के अधीन वीआईएफआर द्वारा एक रूग्ण कंपनी के तौर पर वर्गीकृत किया गया और वह लगभग एक दशक तक ऐसी ही रही। रिलायंस को लोक उद्यमों संबंधी संसदीय समिति की नौवीं रिपोर्ट (2015-16) में रखा गया है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रक्षोपाय महानिदेशक को उसका प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी एचओसीएल ने आधुनिक जिओलाइट कैटेलिस्ट प्रणाली का प्रयोग करके क्यूमिन के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का उन्मयन नहीं किया है।
- vii. कि इससे पता चलता है कि वस्तुतः कथित पाटन से कोई क्षति नहीं हुई है और याचिकाकर्ता माननीय प्राधिकारी के समक्ष गलत तथ्य देकर पाटनरोधी कानूनों का दुरुपयोग कर रहा है। इसके अलावा, इससे अक्षमता से निपटने में एचओसीएल की असमर्थता और बढ़ती हुई मांग का विस्तार करने और उसे हासिल करने में पहल का अभाव प्रदर्शित होती है।
- viii. कि एचओसीएल ने जाँच अवधि सहित हाल के वर्षों में बार-बार और निरंतर संयंत्र को बंद किया है। 2005 से एचओसीएल को भारतीय कानून के तहत एक रूग्ण कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाल में कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय गिरावट के कारण एचओसीएल का फेनोल विनिर्माण संयंत्र फिर से बंद हो गया। इन निरंतर बंदियों से एचओसीएल घरेलू बाजार में आपूर्ति करने में असमर्थ हो गया और परिणामस्वरूप एचओसीएल के कार्यनिष्पादन में नुकसान हुआ। वास्तव में, एचओसीएल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि लम्बे समय तक बंदी कच्ची सामग्री की कमी और अन्य समस्याओं जिनका संबद्ध वस्तु के कथित पाटन से कोई सहसंबंध नहीं है का परिणाम है।
- ix. कि एचओसीएल ने स्वीकार किया है कि रासायनी संयंत्र आज की तारीख में बंद पड़ा है और फिर भी याचिकाकर्ता यह दावा करते हैं कि उनके उत्पादन और बिक्री स्तर कथित पाटन के कारण कम होते रहे हैं।
- x. कि कार्यशील पूंजी की अत्यधिक कमी के कारण भी उत्पादन बंद हुआ है। कंपनी सार्वजनिक डोमेन में रिकार्ड में है कि कोच्ची रिफाइनरी जो कच्ची सामग्री की आपूर्ति कर रही थी, ने 90 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के कारण कंपनी को आपूर्ति जारी रखने से मना कर दिया। अतः पाटनरोधी शुल्क को पुनः लागू करने से संयंत्र को पुनः प्रचालनरत करने में कोई मदद नहीं मिलेगी।
- xi. कि देश में मांग-पूर्ति के बीच काफी अंतर है जिससे आयात अनिवार्य हो जाते हैं।
- xii. कि घरेलू उद्योग को क्षति आयातों के कारण नहीं हुई है बल्कि संसदीय समिति की रिपोर्ट में मुख्य रूप से बताए गए अन्य कारकों जैसे उत्पादन की उच्च लागत, मांग-पूर्ति में भारी अंतर, पुरानी प्रौद्योगिकी, संयंत्र की कमियों, संयंत्र की बंदियों, दूरदर्शिता की कमी और खराब प्रबंधन के कारण हुई है।
- xiii. उत्पादन में संयंत्र के बार-बार और निरंतर बंद होने के कारण नुकसान हुआ है। घरेलू उद्योग ने 22 प्रतिशत बाजार हिस्सा गंवाया है जबकि आयातों ने केवल 4 प्रतिशत बाजार हिस्सा प्राप्त किया है। अधिकांश हिस्सा कोरिया और सिंगापुर के आयातों के पास है।
- xiv. भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र अन्य उत्पादक, एसआई ग्रुप का कार्य निष्पादन काफी अच्छा रहा है जिससे एचओसीएल की आंतरिक कमियों जिनकी वजह से बाजार हिस्सा कम हुआ है, का पता चलता है।
- xv. कि निर्यातकों की अतिरिक्त क्षमता को उनके विरुद्ध नहीं माना जाना चाहिए। किसी कानून या डब्ल्यूटीओ के अधीन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को उसके लिए आवश्यक मात्रा का ही उत्पादन करना चाहिए। यह मान्यता कि विश्व में कोई भी अतिरिक्त क्षमता भारत को प्रभावित करेगी, त्रुटिपूर्ण है और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाती है।

- xvi. कि कारणात्मक संबंध का अभाव है क्योंकि संबंध आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है। कोरिया और अन्य देशों से आयातों का काफी प्रभाव पड़ा है जिसमें संबंध देश शामिल नहीं है। एचओसीएल ने यह माना है कि अन्य देशों और न कि संबंध देशों पर पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाना है, क्योंकि संबंध देशों पर से शुल्क कभी नहीं हटाया गया।

ब.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

66. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में आधार वर्ष के संबंध में पीओआई में वृद्धि हुई है।
- ii. कि थाइलैंड से आयातों में 2011-12 में वृद्धि हुई, 2012-13 में गिरावट आई और तत्पश्चात जाँच अवधि तक वृद्धि हुई। इसके अलावा, पीओआई में आयात 2010-11 में आयातों से काफी अधिक रही थी और इतनी अधिक कि संभावना की स्थिति के प्रयोजनार्थ पाटन और क्षति मार्जिन सिद्ध होता है।
- iii. जापान के संबंध में, यद्यपि वर्तमान अवधि में कोई आयात नहीं हुए हैं, जापान ने तीसरे देशों को भारी मात्राओं का निर्यात किया है, जो पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति और इन वस्तुओं के भारत में प्रवेश के स्थिति में भारी कीमत कटौती, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को दर्शाता है। इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो आयातों की मात्रा में और वृद्धि होगी।
- iv. थाइलैंड के मामले में संबंध आयातों के कारण भारत में समान उत्पाद की कीमतों में कटौती हो रही है। तथापि, जापान के मामले में तीसरे देश को निर्यात ऐसी कीमतों पर हैं कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से वस्तुओं को भारतीय बाजार में बेजा जाएगा और घरेलू उद्योग की कीमत कटौती से नुकसान होगा।
- v. आयातों से घरेलू कीमत में कटौती हो रही है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा।
- vi. यद्यपि अन्य देशों (और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक स्रोतों से सोर्स करने के विकल्प सहित) पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होने से थाइलैंड से आयातों की मात्रा कम है और जापान से कोई आयात नहीं हुए हैं, तथापि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो यह स्पष्ट है कि पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और तेज हो जाएगी और इन देशों से आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होगी।
- vii. घरेलू उद्योग को देश में उत्पादों के निरंतर पाटन के कारण वास्तविक क्षति होना जारी है।
- viii. अग्रिम लाइसेंस के अधीन के मुद्दे संबंधी न्यायशास्त्र में आवश्यक है कि अग्रिम लाइसेंस के अधीन आने वाली आयात मात्रा कीमत संबंधी क्षति पहुंचा रही है। अतः उसे बाहर नहीं रखा जा सकता है।
- ix. एसआई ग्रुप के आयात मुख्यतः निर्यात दायित्व के तहत किए गए शुल्क मुक्त आयात है और इसलिए वर्तमान जाँच के लिए चिंता का विषय नहीं हैं।
- x. निर्दिष्ट प्राधिकारी पर एसआई ग्रुप के शुल्क प्रदत्त और शुल्क मुक्त आयातों को अलग करने या उसका विश्लेषण करने का कोई दायित्व नहीं है।
- xi. मांग और पूर्ति का अंतर देश में उत्पाद के आयात को उचित ठहराता है पाटन को नहीं। जैसा डीएसएम इंडेमिट्यु के मामले में सेस्टेट ने माना है, यदि निर्यातक भारतीय बाजार में जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति करना चाहता है तो ऐसा सामान्य मूल्य के बराबर कीमत पर जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात करके किया जा सकता है और न कि पाटन मूल्य पर और बाजार पर कब्जा करने के लिए।

- xii. पूर्व में पाटनरोधी शुल्क मापदंडों के पूरा होने पर ही लागू किये गये हैं।
- xiii. दावा की गई क्षति प्रौद्योगिकी में विकास के कारण नहीं हुई है। इसके अलावा यह स्थापित सिद्धांत हैं कि घरेलू को यथास्थिति में देखा जाना चाहिए और न कि आदर्श स्थितियों के संदर्भ में।
- xiv. यदि एचओसीएल को रूग्ण उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया था तो इस संबंध में एक विश्लेषण अवश्य किया जाना चाहिए कि क्या वह पाटन के अलावा अन्य कारकों से हुई क्षति के बिना अन्य कारणों की वजह से ऐसी थी।
- xv. कच्ची सामग्री की कमी लम्बे पाटन और परिणामी क्षति के कारण हुई है। एक प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध है।
- xvi. पाटन से क्षति होती है, जिससे लाभप्रदता में कमी आती है परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को घाटा होता है जिससे नकद प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे कंपनी द्वारा कच्ची सामग्री को लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इससे उत्पादन में नुकसान होता है, जिससे क्षमता उपयोग और बिक्री प्रतिकूलतः प्रभावित होती है। परिणामस्वरूप, कम उत्पादन की वजह से उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और नकद प्रवाह भी घाटों से प्रभावित होता है। बढ़ते हुए नकद प्रवाह कच्ची सामग्री लेने की कंपनी की क्षमता को प्रभावित करती हैं और यह चक्र तब तक चलता है जब तक बाजार पाटन से प्रभावित रहता है।
- xvii. एसआई ग्रुप के संबंध में हितवद्ध पक्षों ने कार्यनिष्पादन में अंतर पर ध्यान दिया है जबकि कानून में कार्यनिष्पादन में विकृति (या विकृति की संभावना) की अपेक्षा होती है।
- xviii. अन्य पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति का अर्थ वर्तमान स्रोतों से 'कोई क्षति नहीं या उसकी संभावना' नहीं होता है।
- xix. कि हितवद्ध पक्षों ने मौखिक सुनवाई के समय लोक उद्यम संबंधी संसदीय समिति की समीक्षाओं/सिफारिशों का उल्लेख किया है और उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु को विस्तार से पढ़ा है, जो यह दर्शाने के लिए है जैसे कि संसदीय समिति को वास्तव में एचओसीएल के कार्यनिष्पादन में विकृति के बिल्कुल अलग कारण दिखाई दिये और यह कि एचओसीएल ने गलत ढंग से अपनी समस्याओं के लिए उत्पाद के पाटन को जिम्मेदार ठहराया है।
- xx. पिछले अनेक वर्षों से पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग किसी न किसी स्रोत से अनुचित प्रतिस्पर्धा से पीड़ित रहा है। ऐसा प्राथमिक रूप से वैश्विक बाजार में भारी अतिरिक्त क्षमता और वस्तुओं का पाटन करने की वैश्विक उत्पादकों की क्षमता के कारण है। यदि घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क की मांग नहीं की होती तो एचओसीएल द्वारा उत्पादन का निलंबन उसके पूरे बंद होने में बदल जाता।
- xxi. यदि एचओसीएल द्वारा कोई कुप्रबंधन होता तो संसदीय समिति द्वारा उसपर सही ढंग से कार्रवाई इसलिए की जाती क्योंकि एचओसीएल एक सावर्जनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके अलावा पाटनरोधी के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी कानून के अंतर्गत विहित अपेक्षाओं का पालन करने के बाद ही शुल्क की सिफारिश करेंगे। समिति का यह निष्कर्ष किसी भी तरह से निर्दिष्ट प्राधिकारी की जाँच प्रक्रिया पर प्रश्न नहीं उठाता है।
- xxii. प्रतिवादी हितवद्ध पक्षों के तर्क के विपरीत समिति ने पाटनरोधी शुल्क को हटाये जाने के 'नकारात्मक' प्रभाव को एचओसीएल की निराशाजनक स्थिति के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारकों में से एक बताया है।
- xxiii. पाटन से न केवल एचओसीएल प्रभावित हुई है बल्कि एसआई ग्रुप को भी नुकसान हुआ है। निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया दो कंपनियों के क्षति संबंधी विवरणों की जाँच करें।

अ.3 हितबद्ध पक्षों के प्रकटन के बाद के अनुरोध

67. प्रकटन के बाद के अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने अधिकांशतः क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अपने दृष्टिकोण को दोहराया है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अनुरोध किया है:

- i. कि कीमत कटौती सकारात्मक है और यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो बाजार में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग के साथ इसमें वृद्धि होने की संभावना है।
- ii. कि एचओसीएल ने उत्पाद के भारी पाटन के कारण उत्पादन निलंबित कर दिया जिसने उसकी वर्तमान प्रचालनों को अव्यवहार्य बना दिया था। एचओसीएल व्यवसाय से पूर्णतः बाहर नहीं हुआ है। उसने केवल उत्पादन निलंबित किया है जो पुनः शुरू हो गया है और प्राधिकारी की मांग के अनुसार एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया था।
- iii. कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू विक्रियों, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह की दृष्टि से विकृति आई है। एसआई ग्रुप द्वारा प्रस्तुत सूचना से उसके लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय में भारी कमी का पता चलता है। यद्यपि एसआई ग्रुप एक निजी उद्यम है और एचओसीएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। कंपनी द्वारा उठाए जा रहे वित्तीय घाटों के कारण कंपनी को अपना उत्पादन कम करने को मजबूर होना पड़ा है।
- iv. कि जॉच अवधि के दौरान विक्री प्राप्ति उत्पादन लागत से कम रही है।
- v. कि भारतीय बाजार में उत्पाद के वैश्विक आधिक्य के पाटन के कारण एचओसीएल अपने कार्यनिष्पादन में आगे सुधार नहीं कर पाया और उसे पुनः घाटा हो रहा है।
- vi. कि घरेलू उद्योग को अब भी पाटित संबद्ध वस्तु के आयातों से निरंतर क्षति हो रही है।
- vii. कि सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर भी एचओसीएल को पीओआई में भारी प्रतिकूल कीमत प्रभाव को झेलना पड़ सकता था।
- viii. कि विनिमय दर अस्थिरता, मुद्रास्फीति, उच्च व्याज दर और अस्थिर शेयर बाजार जैसा कोई भी कारक घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है। इनमें से किसी भी कारक में और जहां तक घरेलू उद्योग और वर्तमान उत्पाद का संबंध है कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तथापि, घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में भारी कमी आई है जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि यह विकृति अन्य कारकों की वजह से नहीं आई है।
- ix. कि थाइलैंड से आयात काफी अधिक हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि थाइलैंड के उत्पादकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को भारी क्षति होने की संभावना है।
- x. कि एचओसीएल ने फेनोल और एसीटोन की लागत के आबंटन के लिए किसी अलग पद्धति को नहीं अपनाया है। एचओसीएल ने संगत ढंग से सूचना उपलब्ध कराई है।
- xi. यह कि संगत मापदंडों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है और इस प्रकार कारणात्मक संबंध सिद्ध होता है।
- xii. कि मांग में संकुचन वह संभावित कारण नहीं हो सकता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- xiii. कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को कोई क्षति होने की संभावना नहीं है।
- xiv. कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।
- xv. कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही आगामी भविष्य में किसी परिवर्तन की संभावना है। अतः प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का कारक नहीं है।
- xvi. कि पाटन के तथ्य को प्राधिकारी द्वारा सभी पूर्ववर्ती मामलों में सिद्ध किया गया है। फेनोल और एसीटोन क्षमता का भारी वैश्विक आधिक्य भारत में उत्पाद के पाटन का स्पष्ट कारण है। ऐसे भारी आधिक्य जारी रहने की संभावना है। वास्तव में फेनोल की मांग में एसीटोन की मांग में वृद्धि के अनुपात के बिना वृद्धि होने की संभावना है, जिससे वैश्विक बाजार में एसीटोन की कीमतों पर और दबाव पड़ेगा।

68. प्रतिवादी हितवद्ध पक्षों ने प्रकटन के बाद के अपने अनुरोधों में निम्नानुसार तर्क दिये हैं:

- कि यदि अग्रिम लाइसेंस आयातों में प्रचलित आयात मात्राओं (या कीमतों) से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है, तो पाटनरोधी शुल्क को लगाने से उस क्षति का उपचार नहीं होगा। जब तक कोई व्यापक नीतिगत परिवर्तन नहीं होता है तब तक पाटनरोधी शुल्क को लगाने से अग्रिम लाइसेंस आयातों (चाहे पाटित हों अथवा नहीं) से याचिकाकर्ताओं का कोई संरक्षण नहीं होगा।
- कि आयातों में वृद्धि संभवतः पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन रोक दिए जाने के कारण हुई है। भारत में आयातों की आमद वर्तमान मामले जिसमें घरेलू उद्योग ने पीओआई के दौरान उत्पादन रोक दिया है, में विशेष रूप से पाटन की ओर लक्षित नहीं है – वास्तव में ऐसी प्रतिस्पर्धा केवल एक मुक्त बाजार की संकेतक है। इसके अलावा, जैसा प्राधिकारी ने फेनोल के प्रकटन विवरण के पैरा 71 में नोट किया है मुख्य लाभ पाटनरोधी शुल्क लागू वाले गैर-संबद्ध देशों को हुआ है और न कि संबद्ध देशों को। इस पहलू स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध देशों से कोई मात्रात्मक क्षति नहीं हुई है।
- कि घरेलू उद्योग की निवल विक्री प्राप्ति अब भी इस तथ्य के बावजूद क्षतिरहित कीमत से अधिक बनी हुई है कि पीओआई के एक बड़े हिस्से में एचओसीएल द्वारा उत्पादन रोक दिये जाने के कारण लागत और कीमतें प्रभावित हुई थीं। यह विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातों और घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का स्पष्ट रूप से अभाव है क्योंकि कथित पाटित आयातों से भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग का क्षतिरहित कीमत वसूल किया जाना प्रतिबंधित प्रतीत नहीं होता है। केवल इस जाँच परिणाम को देखते हुए, प्राधिकारी को संबद्ध देशों से शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करने का जाँच परिणाम देना चाहिए।
- यह कि एसआई ग्रुप पीओआई के दौरान पूरा उत्पादन कर रहा था और उसी अवधि के दौरान वह पट्टक कीमत से काफी अधिक उसी बाजार में सापेक्ष रूप से उच्चतर कीमत पर बेचने में सक्षम था, जो दर्शाता है कि पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर कोई ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ा है।
- कि एचओसीएल की बंदी आंतरिक कारणों जैसे प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण का अभाव, कार्यशील पूंजी का संकट और एचओसीएल के बढ़ते हुए व्ययों के कारण रिफाइनरी द्वारा कच्ची सामग्री की आपूर्ति नहीं किया जाना, की वजह से हुई है और संबद्ध देशों से कथित पाटन के कारण नहीं हुई है।

ख. 4 प्राधिकारी द्वारा जाँच

69. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितवद्ध पक्षों और घरेलू उद्योग के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और दिए गए सभी तर्कों की रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानून पर विचार करते हुए जाँच की गई है। तदनुसार, प्राधिकारी शुल्क के समाप्त होने की दशा में संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जाँच करने की कार्यवाही करने से पहले घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, की जाँच करने की कार्यवाही करते हैं।

70. अनुबंध-11 के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

71. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों का मात्रा और कीमत प्रभाव और कीमत तथा लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जाँच करना अपेक्षित है ताकि क्षति की मौजूदगी और पाटन और क्षति, यदि कोई हो, के बीच कारणात्मक संबंधों की मौजूदगी की जाँच की जा सके।

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए आवेदन आरंभ में एचओसीएल और एसआई इंडस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उन्हें इस समीक्षा में क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग माना गया था। तथापि जैसा घरेलू उद्योग द्वारा तर्क दिया गया है दोनों घरेलू उत्पादकों के हालातों को देखने के लिए संभव सीमा तक, दोनों उत्पादकों के कार्यनिष्पादन की अलग-अलग जाँच भी की गई है क्योंकि एचओसीएल पीओआई की पर्याप्त अवधि के दौरान उत्पादन से बाहर रहा था इससे उनका कार्यनिष्पादन काफी अधिक प्रभावित हुआ।

73. शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जाँच की कार्यवाही करने से पहले घरेलू उद्योग के वास्तविक मापदंडों पर पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों की जाँच की गई है।

क. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

(i) आयात मात्राएं और आयातों का हिस्सा

74. आयात मात्राओं और कीमतों की प्रवृत्ति और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आकड़ों की निम्नानुसार जाँच की गई है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई वार्षिकीकृत	पीओआई
1	संबद्ध देश	एमटी	12,047	23,140	5,594	22,872	34,308
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	192	46	190	285
क	जापान	एमटी	0	1,079	48	0	0
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	100	4	0	0
ख	थाइलैंड	एमटी	12,047	22,061	5,546	22,872	34,308
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	183	46	190	285
3	देश जिनपर पाटनरोधी शुल्क लागू है	एमटी	87,580	1,09,181	1,61,481	1,56,774	2,35,162
	प्रवृत्ति		100	125	184	179	269
क	ईयू	एमटी	10,608	8,251	104	14,319	21,479
ख	कोरिया	एमटी	3,425	872	15,533	49,741	74,611
ग	सिंगापुर	एमटी	1,146	897	498	24,776	37,164
घ	दक्षिण अफ्रीका	एमटी	11,223	10,494	14,033	18,604	27,906
ड	ताइवान	एमटी	14,607	38,066	44,861	26,747	40,120
च	यूएसए	एमटी	46,571	50,602	86,451	22,587	33,881
4	अन्य देश	एमटी	18,909	10,720	1,574	5,670	8,505
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	8	30	45
5	कुल	एमटी	1,18,536	1,43,042	1,68,649	1,85,316	2,77,974
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	142	156	235

75. उक्त आकड़ों से पता चलता है कि क्षति जॉच अवधि के दौरान कुल आयातों में आधार वर्ष की तुलना में वार्षिकीकृत आधार पर लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, यद्यपि पीओआई सहित क्षति अवधि के बड़े हिस्से के दौरान जापान से कोई आयात नहीं हुए हैं तथापि थाइलैंड से आयातों में वार्षिकीकृत आधार पर लगभग 90 प्रतिशत की भारी वृद्धि इस अवधि के दौरान हुई है और कुल आयात में उसका हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध वस्तु पर अनेक देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है तथापि नकारात्मक या न्यूनतम सीमा से कम मार्जिनों के कारण कोरिया गणराज्य और सिंगापुर में कुछ प्रमुख निर्यातक शुल्क के दायरे से बाहर हैं। अतः इन देशों से आयातों में इस अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है और कुल आयातों में उनका हिस्सा लगभग 85 प्रतिशत है जबकि अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आई है।

76. हितवद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना अग्रिम लाइसेंस के अधीन काफी मात्रा में आयात हुए हैं और इसलिए क्षति विश्लेषण के लिए आयातों को पृथक् करके विश्लेषण किया जाए। तथापि किसी भी हितवद्ध पक्ष ने अग्रिम लाइसेंस के अधीन आयातों की मात्रा के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

ii) मांग और बाजार हिस्सों का आकलन

77. हितवद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि भारतीय बाजार में मांग और पूर्ति के बीच भारी अंतर है। मांग के आकड़े का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और समस्त स्रोतों से आयातों को जोड़कर किया गया है जो निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई वार्षिकीकृत	पीओआई
	भारत में मांग						
1	घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	77,521	60,189	54,316	37,830	56,745
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	70	49	73
	एचओसीएल	एमटी	***	***	***	***	***
	एसआई ग्रुप	एमटी	***	***	***	***	***
2	कुल आयात	एमटी	89,465	1,07,231	1,35,453	1,63,517	2,45,275
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	120	151	183	274
3	भारत में मांग	एमटी	1,96,057	2,03,231	2,22,965	2,23,146	3,34,719
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	114	114	171

78. उक्त आकड़ों से पता चलता है कि यद्यपि मांग पिछले दो वर्षों से समान रही है तथापि विशेष रूप से पीओआई के दौरान मुख्य रूप से एचओसीएल की बिक्री में गिरावट के कारण आयातों में वृद्धि हुई है और घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है। पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में विभिन्न पक्षों के बाजार हिस्से की प्रवृत्ति निम्नानुसार थी:

विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई वार्षिकीकृत	पीओआई
घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	%	40%	30%	24%	17%	17%
एचओसीएल	%	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	%	***	***	***	***	***
संबद्ध देशों से पाटित आयात	%	6%	11%	3%	10%	10%
देश जिनपर पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	45%	54%	72%	70%	70%
अन्य देश	%	10%	5%	1%	3%	3%
कुल	%	100%	100%	100%	100%	100%

79. उक्त आकड़ों से पता चलता है कि कुल मांग में घरेलू उत्पादकों के हिस्से में एचओसीएल के घाटे के कारण मुख्य रूप से गिरावट आई है क्योंकि अन्य उत्पादक लगभग पूरी क्षमता का उत्पादन कर रहा है। थाइलैंड से आयातों के हिस्से में 2012-13 में गिरावट के बाद वृद्धि हुई है। परंतु प्रमुख लाभ उन देशों को हुआ जिन पर शुल्क लागू है, जो देश में बाजार मांग के लगभग 70 प्रतिशत पर काबिज हैं।

ख. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

i) आयात कीमतों की प्रवृत्ति

80. डीजीसीआईएंडएस के आकड़ों के अनुसार पीओआई के दौरान विभिन्न देशों से आयातित संबद्ध वस्तु की आयात कीमतें निम्नानुसार हैं:

देश	कीमत (रू./किग्रा.)				
	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई वार्षिकीकृत	पीओआई
संबद्ध देश	82	77	83	91	91
जापान	-	74	95	-	-
थाइलैंड	82	77	83	91	91
देश जिनपर पहले से शुल्क लागू है	74	74	80	88	88
ईयू	73	85	59	88	88
कोरिया गणराज्य	74	86	86	91	91
सिंगापुर	82	94	90	83	83
दक्षिण अफ्रीका	67	69	71	81	81
ताइवान	80	78	81	92	92
यू एस ए	74	69	80	87	87
अन्य	77	84	78	92	92
कुल योग	75	75	80	88	88

81. उक्त आकड़े दर्शाते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर, जहां पीओआई के दौरान कीमतें कम थीं, को छोड़कर सभी देशों से आयातों की सीआईएफ कीमतें पीओआई के दौरान काफी कम परिवर्तित हुई हैं।

ii) पाटित आयातों का कीमत कटौती प्रभाव

82. संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कीमत कटौती प्रभाव की जाँच करने के लिए आयातों के पंधुच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई है।

विवरण	यूओएम	जापान	थाइलैंड
पाटित आयातों की पंधुच कीमत	रू./एमटी	कोई आयात नहीं	1,01,241
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./एमटी		***
कीमत कटौती (एडीडी के बिना)	रू./एमटी		***
	%		0-10%
कीमत कटौती (एडीडी सहित)	रू./एमटी		***
	%		0-10%

83. आकड़ों से पता चलता है कि थाइलैंड से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में मामूली कटौती हुई है।

(iii) पाटित आयातों के कम कीमत पर बिक्री के प्रभाव

84. पाटित आयातों के पंधुच मूल्य की तुलना एचओसीएल और एसआई ग्रुप दोनों की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग हेतु निर्धारित क्षतिरहित कीमत के साथ की गई है ताकि यह देखा जाए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर काफी कम कीमत पर बिक्री का प्रभाव पड़ा है।

विवरण	यूओएम	जापान	थाइलैंड
क्षतिरहित कीमत	रू./एमटी	***	***
पाटित आयातों की पंधुच कीमत	रू./एमटी	कोई आयात नहीं	1,01,241
कम कीमत पर बिक्री एडीडी के बिना	रू./एमटी		***
	%		0-10%
कम कीमत पर बिक्री एडीडी सहित	रू./एमटी		***
	%		0-10%

85. उक्त आकड़ों से पता चलता है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर बिल्कुल मामूली कम कीमत पर बिक्री प्रभाव पड़ा है। तथापि निवल बिक्री प्राप्ति इस तथ्य के बावजूद क्षतिरहित कीमत से अधिक रही है कि पीओआई के बड़े हिस्से में एचओसीएल द्वारा उत्पादन रोक देने के कारण लागत और कीमतें प्रभावित हुई थीं।

(iv) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

86. चूंकि घरेलू उद्योग की लागत पीओआई के दौरान एक उत्पादक द्वारा उत्पादन बंद करने और काफी कम क्षमता उपयोग के कारण काफी प्रभावित हुई है, इसलिए यह देखने के लिए कि क्या पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी ह्रास हुआ है, प्रवृत्तियों का तर्कसंगत विश्लेषण संभव नहीं हुआ। तथापि, क्षतिरहित कीमत, जो लागत का एक संकेतक है, की आयातों के पंधुच मूल्य और बिक्री प्राप्ति के साथ तुलना से पता चलता है कि कीमतों का ह्रास नहीं हुआ है। इसके अलावा, अन्य घरेलू उत्पादक उसी अवधि के दौरान पंधुच कीमत से अधिक समान बाजार में सापेक्ष रूप से उच्चतर कीमतों पर बिक्री करने में समर्थ रहा है जो दर्शाता है कि पाटित आयातों से घरेलू कीमतों पर कोई ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव नहीं पड़ा।

ग. घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक मापदंड

87. घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न वास्तविक कार्यनिष्पादन मापदंड निम्नानुसार हैं:

(i) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

88. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग (एचओसीएल) का उत्पादन पीओआई के दौरान काफी प्रभावित हुआ था, बिक्री, क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में दोनों घरेलू उत्पादकों की भी अलग-अलग निम्नानुसार जाँच की गई है ताकि यह देखा जा सके कि क्या दोनों उत्पादकों का कार्यनिष्पादन पाटित आयातों से प्रभावित हुआ है।

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई वार्षिकीकृत	पीओआई
क्षमता डीआई	एमटी	74,200	74,200	76,750	63,417	95,125
प्रवृत्ति		100	100	103	85	128
एचओसीएल	एमटी	40,000	40,000	40,000	40,000	60,000
एसआई ग्रुप	एमटी	34,200	34,200	36,750	36,750	55,125

उत्पादन डीआई	एमटी	80,796	67,500	59,921	43,537	65,306
प्रवृत्ति		100	100	89	64	97
एचओसीएल	एमटी	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	एमटी	***	***	***	***	***
क्षमता उपयोग डीआई		109%	91%	78%	69%	69%
प्रवृत्ति		100	100	86	75	75
एचओसीएल	%	***	***	***	***	***
एसआई ग्रुप	%	***	***	***	***	***
घरेलू बिक्रियां डीआई	एमटी	77,521	60,189	54,316	37,830	56,745
प्रवृत्ति		100	100	90	63	94
एचओसीएल	एमटी	***	***	***	***	***
एसआई	एमटी	***	***	***	***	***
आबद्ध बिक्री	एमटी	2,499	5,942	6,870	6,525	9,787
प्रवृत्ति		100	100	116	110	165
एचओसीएल	एमटी	***	***	***	***	***
एसआई	एमटी	***	***	***	***	***

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि एसआई ग्रुप पूरी क्षति जॉच अवधि के दौरान अपनी लगभग पूर्ण क्षमता पर प्रचालन कर रहा था तथापि एचओसीएल के उत्पादन में 2011-12 से भारी गिरावट आई। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एचओसीएल की उत्पादन सुविधा पीओआई के दौरान केवल 119 दिनों के लिए प्रचालनरत रही थी जिससे जॉच अवधि के दौरान उत्पादन में कमी और कम क्षमता उपयोग हुआ।

90. हितवद्ध पक्षों ने यह तर्क दिया है कि एचओसीएल का कार्यनिष्पादन अनेक आंतरिक कारणों से लम्बे समय से प्रभावित रहा है। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कार्यनिष्पादन अनेक स्रोतों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण प्रभावित हुआ है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूरी क्षति अवधि के दौरान कुछ देशों से कुछेक उत्पादकों को छोड़कर संबद्ध देशों सहित अधिकांश प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों पर शुल्क लागू था। इसके अलावा दूसरे घरेलू उत्पादक का लगभग पूर्ण क्षमता पर उत्पादन घरेलू उद्योग के इस तर्क का समर्थन करता प्रतीत नहीं होता है यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कतिपय उतार-चढ़ाव से उत्पादन और क्षमता उपयोग प्रभावित हो सकता है जैसा कि एसआई ग्रुप के मामले में देखा गया है।

(ii) लाभ/हानि, निवेशपर आय और नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

91. संबद्ध वस्तु के संबंध में क्षति जॉच अवधि के दौरान एचओसीएल का वित्तीय कार्यनिष्पादन नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

लाभ/हानि - घरेलू	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई वार्षिकीकृत	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	114	129	129
एचओसीएल	रू./एमटी	***	***	***	***	***
एसआई	रू./एमटी	***	***	***	***	***

विक्री कीमत	रू./एमटी	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	100	104	117	117
एचओसीएल	रू./एमटी	***	***	***	***	***
एसआई	रू./एमटी	***	***	***	***	***
लाभ/हानि	रू./एमटी	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		100	100	-215	-294	-294
एचओसीएल	रू./एमटी	***	***	(***)	(***)	(***)
एसआई	रू./एमटी	***	***	(***)	***	***
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति		100	100	-150	-108	-163
एचओसीएल	%	***	***	(***)	(***)	(***)
एसआई	%	***	***	(***)	***	***

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचओसीएल का संयंत्र पीओआई के 18 महीनों में से केवल 119 दिनों तक प्रचालन में रहा था। अतः, संयंत्र के लम्बे समय तक बंद रहने से लागत काफी अधिक प्रभावित हुई है और उससे वास्तविक उत्पादन लागत प्रदर्शित नहीं होगी। पूर्ववर्ती वर्ष के आकड़े दर्शाते हैं कि एचओसीएल अपनी क्षमता के पूर्ण उपयोग करने के समय तक अपने घरेलू प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उच्चतर लाभ मार्जिन के साथ संबद्ध वस्तु का एक कुशल उत्पादक था। एचओसीएल की क्षमताउपयोग में 2012-13 के बाद से गिरावट शुरू हुई जिसके बाद 2012-13 से मार्जिनों में कमी और अनुवर्ती घाटे हुए। इसी के साथ अन्य घरेलू उत्पादक 2012-13 जब उसने क्षमता उपयोग में मामूली गिरावट का सामना किया को छोड़कर पूरी अवधि में सकारात्मक लाभ मार्जिन अर्जित कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि एचओसीएल को हुए घाटे विचाराधीन अवधि के दौरान उत्पादन और विक्री करने में उसकी अक्षमता के कारण हुए हैं। अतः क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में कमी के कारणों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

93. चूंकि एक घरेलू उत्पादक अर्थात् एचओसीएल का संयंत्र विभिन्न कारणों की वजह से लम्बी अवधि के लिए प्रचालन में नहीं था अन्य अनिवार्य मापदंड इस परिदृश्य में असंगत हैं और उनकी जाँच नहीं की गई है।

ट. क्षति और कारणात्मक संबंध का समग्र आकलन

94. उक्त रूप से क्षति संबंधी मापदंडों की जाँच से पता चलता है कि एक घरेलू उत्पादक अर्थात् एचओसीएल के उत्पादन में भारी कमी हुई जिसके चलते वित्तीय घाटा हुआ। पूर्ववर्ती खंड में यह सिद्ध हुआ है कि जापान से कोई आयात नहीं हुए थे। थाइलैंड से आयात पाटित कीमतों पर थे परंतु पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से थोड़ा अधिक है। अन्य घरेलू उत्पादक लगभग पूरी क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं और सकारात्मक लाभ मार्जिन कमा रहे हैं। इन परिस्थितियों में इस बात की जाँच करना अनिवार्य है कि क्या उत्पादन में कमी और परिणामी वित्तीय घाटा संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुआ है या अन्य कारणों की वजह से।

95. एचओसीएल के उत्पादन घाटे और वित्तीय घाटों के रूप में परिणामी क्षति के संबंध में प्रतिवादी हितवद्ध पक्षों ने संसदीय समिति की रिपोर्टों और अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना को उद्धरित करते हुए यह तर्क दिया है कि एचओसीएल की उत्पादन इकाई उसकी आंतरिक अक्षमताओं और प्रबंधन संबंधी समस्याओं और न कि पाटन की वजह से बंद हुई है। यह भी बताया गया है कि आधुनिकीकरण में इकाई के अक्षम होने और आर्थिक आकार को बढ़ाने और कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता की वजह से संयंत्र बंद हुआ और संबद्ध देशों से आयातों के कारण से नहीं।

96. घरेलू उद्योग ने प्रकटन के बाद के अनुरोधों में तर्क दिया है कि एचओसीएल ने पीओआई के दौरान उत्पादन को रोक दिया क्योंकि पाटित आयातों के कारण उत्पादन और विक्री अव्यवहार्य हो गई थी और संयंत्र पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। यह भी बताया गया है कि एचओसीएल ने कोचीन रिफाइनरी से कच्ची सामग्री की आपूर्ति की कतिपय व्यवस्थाओं के साथ हाल में उत्पादन पुनः शुरू किया है।

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एचओसीएल की उत्पादन इकाई को फेनोल की 40,000 एमटी क्षमता और एसीटोन की 45000 एमटीएस क्षमता के साथ 1980 के उत्तरार्द्ध में स्थापित किया गया था। क्षमता और प्रौद्योगिकी संभवतः उस समय उपलब्ध मांग के परिदृश्य और प्रौद्योगिकी पर आधारित थी। तत्पश्चात्, मांग में भारी वृद्धि हुई और प्रौद्योगिकी में भी सुधार हुआ जैसा संसदीय समितियों की रिपोर्ट और प्राधिकारियों के समक्ष कंपनी के अनुरोधों से नोट किया गया है। परंतु कंपनी विभिन्न कारणों से संयंत्र की क्षमता में वृद्धि या आधुनिकीकरण नहीं कर पाई। उत्पादन बढ़ाने और आधुनिकीकरण में संयंत्र की अक्षमता और अनेक देशों से पाटन से कंपनी के कार्यनिष्पादन पर प्रभाव पड़ा और वर्ष 2002 से शुरू होकर अनेक देशों से फेनोल और एसीटोन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया था। तथापि, एचओसीएल के निरंतर घाटों के कारण उसे 2005 में रूपण इकाई घोषित कर दिया गया और वह अब भी बीआईएफआर के अधीन है।

98. काफ़ी कर्मचारियों के साथ अनेक अन्य उत्पादों में शामिल कंपनी की रासायनी इकाई 2013 से बंद पड़ी है। तथापि कोच्ची इकाई जो कतिपय अन्य उत्पादों के साथ फेनोल और एसीटोन उत्पादित करती है, कतिपय अवधि के लिए पूर्ण क्षमता पर उत्पादन कर रही थी परंतु वह भी कार्यशील पूंजी की समस्याओं से ग्रस्त हो गई क्योंकि इस इकाई के लाभ पहले अन्य बंद इकाइयों के स्थिर व्ययों को उठा रहे थे। कच्ची सामग्री की आपूर्ति के लिए कोचीन रिफाइनरी के 90 करोड़ रुपये से अधिक के बकायों के कारण रिफाइनरी ने इस इकाई को कच्ची सामग्री की आपूर्ति रोक दी है जिससे 2015 के मध्य से कोच्ची संयंत्र का उत्पादन भी रुक गया है।

99. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कतिपय स्रोतों जिन्हें संबंधित जॉच में पाटन करता नहीं पाया गया था, को छोड़कर सभी प्रमुख स्रोतों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। इसलिए उन आयातों को इस उत्पादक द्वारा उठाई गई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

100. हितवद्ध पक्षों ने आधुनिकीकरण के अभाव और कुशल उत्पादन पद्धतियों को अपनाने और उत्पादन क्षमता को आर्थिक आकार नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया है जैसा विभिन्न रिपोर्टों और प्राधिकारियों के समक्ष उनकी स्वीकृति से नोट किया गया है, क्षति के एक कारण के रूप में बताया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी की उत्पादन सुविधाएं पुरानी हैं और अनेक स्रोतों से पाटन सहित विभिन्न कारकों की वजह से उनमें कोई खास आधुनिकीकरण नहीं हुआ है।

101. अतः एचओसीएल की स्थिति का समग्र आकलन दर्शाता है कि संयंत्र का बंद होना संबद्ध देशों से पाटित आयातों के वजाय उसकी कार्यशील और प्रबंधन से सीधे जुड़ा हुआ है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण पूरी क्षति जॉच अवधि के लिए इन आयातों के विरुद्ध उपलब्ध था। उक्त को ध्यान में रखते हुए पीओआई के दौरान कंपनी के कार्य निष्पादन के लिए संबद्ध देशों से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। केवल यही तथ्य कि एचओसीएल ने कोचीन रिफाइनरी के साथ कच्ची सामग्री की आपूर्ति के लिए कतिपय करार के साथ उत्पादन पुनः शुरू करने का प्रयास किया है यह भी दर्शाता है कि उत्पादन को रोकना जाना कच्ची सामग्री और कार्यशील पूंजी से जुड़े मुद्दों के कारण था और संबद्ध देशों से पाटित आयात इसका मुख्य कारण नहीं थे।

102. अन्य घरेलू उत्पादक अर्थात् एसआई ग्रुप के कार्यनिष्पादन में कोई खास खराबी नहीं आई है। उनका उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्री स्थिर बनी हुई है और लाभप्रदता 2011-12 के स्तर के आस-पास बनी हुई है। इस कंपनी का कार्यनिष्पादन इस अवधि के दौरान कुछ खास प्रभावित हुआ प्रतीत नहीं होता है यद्यपि पर्याप्त आयात समान कीमतों पर अनेक देशों से हो रहे हैं।

103. अतः प्राधिकारी को कथित पाटित आयात और घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई समग्र क्षति के बीच कोई खास कारणात्मक संबंध नहीं मिला है।

ठ. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा

104. चूंकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण नहीं हुई प्रतीत होती है, इसलिए क्षति मार्जिन का निर्धारण असंगत है। तथापि, नियमावली के संगत प्रावधानों के आधार पर और पीओआई के दौरान उत्पादन में घाटे और संबद्ध देशों से आयातों के पंहच मूल्य पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत के अनुसार, आयातों का क्षति मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

विवरण	यूओएम	जापान	थाइलैंड
क्षतिरहित कीमत	रू./एमटी	***	***
पाटित आयातों की पंधुच कीमत	रू./एमटी	कोई आयात नहीं	1,01,241
क्षति मार्जिन	रू./एमटी		***
	%		0-10%

105. यद्यपि, भारत औसत पंधुच कीमत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित भारत औसत क्षतिरहित कीमत से मामूली रूप से कम है तथापि घरेलू उद्योग की भारत औसत विक्री कीमत क्षतिरहित कीमत से अधिक पाई गई थी।

106. घरेलू उद्योग तथा प्रतिवादी हितवद्ध पक्षों ने प्रकटन के बाद के अपने अनुरोधों में क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के संबंध में कतिपय मुद्दों को उठाया है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III में दी गई पद्धति के अनुसार और घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की गई है इसलिए एनआईपी के किसी पुनरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्षति के जारी रहने की संभावना

107. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यातों के आधार पर वर्तमान कीमत कटौती और/या संभावित कीमत कटौती से पता चलता है कि यदि शुल्क को हटाया जाता है तो इन वस्तुओं से घरेलू उद्योग को क्षति होगी। दूसरी ओर प्रतिवादी हितवद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हुई है और घरेलू उद्योग अपनी आंतरिक समस्याओं से ग्रस्त है। यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों में प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के उनकी अपनी आवद्ध खपत और अन्य वचनबद्ध क्रेताओं को पूर्ववर्ती प्रतिबद्धताओं के कारण संबद्ध देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है।

108. प्रकटन के बाद के अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने अपने मत को दोहराया है और यह तर्क दिया है कि मौजूदा शुल्क की अवधि समाप्त होने पर संबद्ध देश से निर्यातक भारतीय बाजार में अपने उत्पादन को आगे चैनलाइज करेंगे क्योंकि उनके पास पहले से आधिक्य क्षमताएं हैं और वे अत्यधिक निर्यातोन्मुखी हैं। यह तर्क दिया गया है कि थाइलैंड के उत्पादक अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। यह आधिक्य क्षमता अपने निर्यातों को बढ़ाने में प्रयुक्त होगा और भारत की अधिक मांग की वजह से वह उनकी पहली पसंद होगा। आयात अब भी पीओआई के बाद कुछ बढ़कर पाटित कीमतों पर जारी हैं। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद ऐसी स्थिति की मौजूदगी क्षति की संभावना का स्पष्ट संकेत देती है।

109. प्रतिवादी हितवद्ध पक्षों ने प्रकटन के बाद के अपने अनुरोधों में तर्क दिया है कि पीओआई के बाद के आकड़ों में थाइलैंड से आयातों की मात्रा में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है और जापान से आयात शून्य बने हुए हैं यद्यपि घरेलू उद्योग के संयंत्र के बंद होने से मांग और आपूर्ति में भारी अंतर हो गया है। सभी स्रोतों से आयातों के कीमत स्तर में कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट के कारण कीमतों में कमी आई है। यह भी तर्क दिया गया है कि तीसरे देशों में प्रमुख बाजारों में क्रेताओं को पूर्व वचनबद्धता और अपनी स्वयं की आवद्ध खपत के कारण थाइलैंड से पाटन की पुनरावृत्ति और परिणामी क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

110. जैसा पहले नोट किया गया है पीओआई के दौरान जापान से संबद्ध वस्तु का कोई पाटन नहीं हुआ था और थाइलैंड से आयातों का पाटन मार्जिन पीओआई के दौरान न्यूनतम सीमा से मामूली अधिक था। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से, उन देशों में प्रमुख उत्पादकों की क्षमताओं और मांग पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तीव्र पाटन की कोई आसन्न संभावना नहीं है। पीओआई के बाद के आकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के संयंत्र बंद होने से उत्पन्न मांग-पूर्ति के अंतर को भरने के लिए आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। समस्त स्रोतों से आयातों के कीमत स्तर में कच्ची सामग्री की कीमतों में कमी के कारण गिरावट आई है।

111. घरेलू उत्पादन के पीओआई के बाद (अक्टूबर-मार्च 2015) के आकड़ों से पता चलता है कि एचओसीएल पूरी अवधि में उत्पादन से बाहर था परंतु अन्य उत्पादक (एसआई ग्रुप) लगभग पूरी क्षमता पर प्रचालन कर रहा था। इसके अलावा पूर्ववर्ती खंड का विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि एचओसीएल का उत्पादन मुख्यतः कच्ची सामग्री की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता और उसके कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ता के बकायों से उत्पन्न आंतरिक समस्याओं के कारण रोका गया था। अतः, प्रश्न यह उठता है कि क्या यदि शुल्क को जारी रखा जाता है तो कंपनी अपने उत्पादन को पुनरुज्जीवित करने की स्थिति में होगी।

112. विभिन्न कारकों और प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना की जाँच से यह पता चलता है कि कार्यशील पूँजी और प्रबंधन की समस्याओं का समाधान किये बिना कंपनी पाटनरोधी संरक्षण दिए जाने पर भी उत्पादन और बिक्री को पुनरुज्जीवित करने की स्थिति में नहीं होगी। हाल में कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ता के साथ कतिपय समझौते सहित उत्पादन की पुनः शुरुआत अब भी स्थिर नहीं हुई है। जाँच अवधि के दौरान संबद्ध देशों सहित विभिन्न स्रोतों से आयातों का प्रभाव नगण्य था। अतः इस मामले के वास्तविक तथ्यों में प्राधिकारी का मत है कि यद्यपि समग्र रूप से घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहेगा परंतु वह संबद्ध देशों से पाटन के कारण नहीं है और उपाय को जारी रखने से जब तक अन्य उपाय न किए जाए एचओसीएल के पुनरुद्धार में मदद नहीं मिलेगी।

ड. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

113. पाटन-रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय घरेलू बाजार में खुले और उचित प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण बहाल किया जा सके। तथापि, वर्तमान मामले में एक घरेलू उत्पादक ने समीक्षाधीन देशों से पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से उत्पादन बंद कर दिया है। दूसरा घरेलू उत्पादक समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिक प्रभावित नहीं हुआ है। घरेलू बाजार में मांग पूर्ति में भारी अंतर है जिससे आयात आवश्यक हैं। अतः यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर शुल्क को आगे पाँच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है तो न तो संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों न ही प्रयोक्ता उद्योग के हितों को कोई लाभ होगा।

ण. निष्कर्ष और सिफारिशें

114. प्राधिकारी ने विधि के अनुसार इस समीक्षा जाँच की शुरुआत और संचालन किया और वर्तमान पाटन, क्षति और पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध और शुल्क हटायें जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जाँच की। पूर्वोक्त पैराग्राफों में यह सिद्ध हुआ है कि समीक्षा अवधि के दौरान जापान से संबद्ध वस्तु का कोई पाटन नहीं हुआ था। थाइलैंड से पाटन जारी रहा परंतु अत्यंत कम स्तर पर। यह भी पाया गया कि यद्यपि यदि शुल्क हटाया जाता है तो थाइलैंड से आयात वर्तमान स्तर पर जारी रह सकते हैं और जापान से कुछ आयात हो सकते हैं, तथापि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के भारी पाटन की पुनरावृत्ति होने की कोई आसन्न संभावना नहीं है। यह भी सिद्ध हुआ है कि समीक्षा अवधि के दौरान यद्यपि घरेलू उद्योग को समग्र रूप से क्षति हुई है तथापि यह क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से एचओसीएल के कारण हुई है। अन्य घरेलू उत्पादकों के कार्यनिष्पादन पर समीक्षा अवधि के दौरान कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है और मामूली गिरावट, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि आयात समान कीमत स्तर पर अन्य देशों से हो रहे हैं।

115. जाँच से यह भी पता चला है कि यदि शुल्क की अवधि बढ़ाई जाती है तो एचओसीएल ऐसे स्तर तक अपने उत्पादन का पुनरुद्धार नहीं कर सकेगा जहां वह व्यवहार्य हो जब तक कंपनी की समस्याओं के दीर्घावधिक समाधान के रूप में कंपनी को प्रभावित करने वाले अन्य मूलभूत मुद्दों का समाधान न किया जाए। चूंकि दो में से एक घरेलू उत्पादक उत्पादन नहीं कर रहा था इसलिए देश में मांग और पूर्ति के बीच अंतर में वृद्धि हो गई। अतः यदि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर शुल्क को आगे पाँच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है तो न तो संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों न ही प्रयोक्ता उद्योग के हितों को कोई लाभ होगा।

116. अतः प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 120/2010-सीमाशुल्क दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 द्वारा लागू किए गए जापान और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश नहीं करते हैं।

117. निर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) में दायर की जाएगी।

ए. के. भल्ला , अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2016

FINAL FINDING**Subject: Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of Phenol originating in or exported from Japan and Thailand.**

No. 15/05/2015-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

1. Having regard to the above Rules the Designated Authority had initiated the original investigation concerning imports of Phenol, originating in or exported from Japan and Thailand, vide Notification No. 14/27/2009-DGAD dated 11th August 2009. The Designated Authority notified the Preliminary Findings recommending provisional anti-dumping duties on 3rd February, 2010. Provisional duties were imposed on 19th April 2010. The Final Findings Notification was issued by the Authority on 8th October 2010 recommending imposition of definitive duty on the imports of Phenol, originating in or exported from Japan and Thailand. Definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 120 /2010-Customs dated 1st December 2010 for a period of 5 years from 19th April 2010, i.e., upto 18th April 2015.
2. M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited (hereinafter also referred to as HOCL), M/s. SI Group India Ltd (hereinafter also referred as SI Group), filed an application before the Designated Authority for initiating a combined sunset review of the anti-dumping duties on import of Phenol and Acetone from Thailand and Japan, imposed vide Notification No. 120 /2010-Customs dated 1st December 2010 and No. 36/2011-Customs dated 18th April, 2011. The petitioners alleged likelihood of continuation of dumping of the above goods, originating in or exported from Japan and Thailand (herein after referred to as the subject countries) and consequent injury to the domestic industry and requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.
3. In accordance with section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation, vide Notification No. 15/05/2015-DGAD dated 9th April 2015 to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in respect Phenol (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from the subject countries, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The duty was extended by the Department of Revenue till 18th April 2016, vide notification no. 14/2015-Customs (ADD), dated 17th April 2015. The time period for completion of the investigation and notification of final finding of the Authority was extended by the Central Government till 8th July 2016, in terms of Rule 17 of the Rules.
4. Apart from the subject countries, antidumping duties are also in force on the subject goods originating in or exported from the European Union, Singapore, Korea RP, Chinese Taipei, USA and South Africa. The scope of the present review is with respect to the duties in force on the import of the subject goods, originating in or exported from Japan and Thailand and covers all aspects of the previous investigation.

B. Procedure

5. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - i. The Embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the sunset review investigations in accordance with Rule 6(2).
 - ii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

- iii. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known manufacturers/exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority by the petitioner) and provided opportunity to make its views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4).
 - a. PTT Phenol Co., Ltd. (PPCL)
 - b. Chiba Phenol Co. Ltd. Shiodome
 - c. Mitsubishi Chemicals
 - d. Mitsui & Co., Ltd. ("MBK"), Japan
 - e. M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Limited, Singapore
 - f. Mitsubishi Chemical Corporation ("MCC")
 - g. Sunitomo Corporation
 - h. Mitsui Chemicals, Inc.
- iv. The following producers/exporters of the subject goods in the subject countries have filed their questionnaire responses:
 1. M/s. PTT Phenol Company Limited, Thailand (Producer)
 2. M/s. MITSUI CHEMICALS, INC., JAPAN (Producer)
 3. M/s. MITSUI & CO., LTD., JAPAN, (Exporter)
 4. M/s. MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD., Singapore (Exporter)
- v. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known importers/consumers (whose names and addresses were made available to the authority by the applicants) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter, in accordance with the Rule 6(4):
 1. M/s. C.J. Shah and Company
 2. M/s. Haresh Kumar & Co., Mumbai
 3. M/s. PCL Oil & Industries
 4. M/s. Kantilal Manilal & Co. Pvt. Ltd.
 5. M/s. Sonkamal Enterprises, Mumbai
 6. M/s. Khetan Brothers
 7. M/s. Shubham Dyes & Chemicals Limited
 8. M/s. Acron Enterprises
 9. M/s. Naiknavare Chemicals Limited
 10. M/s. Paras Dyes & Chemicals
 11. M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited, Gujarat
 12. M/s. United Phosphorus Ltd., Mumbai
 13. M/s. Resins & Plastic Ltd.
 14. M/s. Kailash Polymers
 15. M/s. Centrum Metalics Pvt. Ltd.
 16. M/s. Wonder Laminates Pvt. Ltd.
 17. M/s. Meghdev Enterprises
 18. M/s. Satguru International
 19. M/s. Bleach Marketing Pvt. Ltd.

20. M/s. Karmen International (P) Ltd.
 21. M/s. High Polymer Labs Ltd.
 22. M/s. Rainbow colours & Chemicals
 23. M/s. Krishna Antioxidants Pvt. Ltd.
 24. M/s. NGP Industries Ltd.
 25. M/s. Farmson Pharmaceutical Gujrat Ltd.
 26. M/s. India Glycols Ltd.
 27. M/s. Singh Plasticisers and Resins (I) Pvt.
 28. M/s. National Plywood Industries Ltd.
 29. Kundan Rice Mills Ltd.
- vi. Only one of the importers of the subject goods, i.e. M/s. Century Ply Board Limited, has filed certain submissions without filing any questionnaire response in this matter.
 - vii. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation was April 2013 –September, 2014 (18 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.
 - viii. Transaction-wise imports data for the period of investigation and preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and has been relied upon for the analysis in this investigation.
 - ix. Exporters, producers, importers and other parties concerned with the subject goods, who have neither responded to the Authority, nor supplied information relevant to this investigation, have not been treated as interested parties in this investigation.
 - x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties, in the form of a public file kept open for inspection by the other interested parties as per Rule 6(7).
 - xi. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
 - xii. The Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in public hearings held on 20th January 2016. All the interested parties attending the hearings were requested to file written submissions/rejoinders of the views expressed orally.
 - xiii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation have been examined and addressed in this finding.
 - xiv. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon which these findings are based. The Authority conducted on-the-spot verification at the premises of the domestic industry and the cooperating producers and exporters to the extent considered relevant and necessary. Additional/supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.
 - xv. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
 - xvi. In accordance with the Rules the Authority issued a disclosure statement containing all essential facts of the case on 17.06.2016 for the comments of the interested parties. The comments of the interested parties, to the extent they are relevant, have been addressed in this finding in appropriate places.

- xvii. *** in this finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xviii. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.60.76 = 1 US\$.

C. Scope of Product under consideration and like article

6. The product under consideration in the Final Findings of the original investigation of Phenol dated 8th October, 2010 was described as follows:

"The product under consideration is 'Phenol'. It is an organic chemical, also known as Carboic Acid and used in the manufacture of Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide and downstream chemicals. Phenol is classified under Chapter 29 & 27 of Custom Tariff Act under the sub-heading 29071110, 27079900 respectively. The customs classification is however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. It is a basic organic chemical, marketed in two grades, viz., Crystalline and Hydrated. The two grades are differentiated on the basis of flow characteristics of Phenol. It is marketed in two forms- loose/ bulk and packed."

7. Petitioners have submitted that the Phenol produced by them are like article to the Phenol imported from the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported products and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably.
8. The product under consideration is classified under Chapter 29 and 27 (Phenol) of the Custom Tariff Act under the subheadings 29071110 and 27079900.
9. No relevant submission has been made by the producers/exporters/ importers/other interested parties with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article. This being the sunset review investigation, the Authority holds that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that of the original investigation.

D. Domestic Industry and Standing

10. As noted earlier, a combined petition for the sunset review of the antidumping duty on Phenol and Acetone was filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) and M/s. SI Group India Ltd. (SI Group). The Petitioners are the only producers of Phenol and Acetone in India and therefore, account for total Indian production. At the stage of initiation, it was submitted by the petitioners that M/s. SI Group had imported these goods from several countries, including subject countries, both under duty free and duty paid schemes for captive consumption only and the imported goods were not sold in the domestic market. Pending further inquiry, the Authority, considered, at the stage of initiation, SI Group as an eligible domestic producer to be a constituent of domestic industry.

D.1 Views of the opposing interested parties

11. The opposing interested parties, in their submissions, have strongly argued for exclusion of SI Group from the scope of domestic industry for the purpose of the injury investigation and have *inter alia* submitted as under:
- That SI Group has been excluded from domestic industry in the past on account of imports, which have been made in the present investigation also to the tune of 20,000 MT in the POI. It has been submitted that out of several investigations carried out by the Designated Authority in most of the original investigations SI Group had been excluded from the scope of the domestic industry on account of imports. Therefore, SI Group's participation in this anti-dumping investigations has been highly inconsistent.
 - That imports of SI Group account for large share of production and sales made by domestic industry. SI Group has imported from sources of alleged dumping and has benefitted by trying to shield itself by partaking in dumping activities.
 - That whether the imports are for captive consumption or commercial sales is irrelevant since any imports directly or indirectly impact the commercial market in India. Even if SI Group used most of imports for captive consumption, it freed up production and inventory of the product under

consideration for commercial sales, while also at the same time ensuring that the captive consumption was substituted by cheap dumped imports.

- iv. that while it is undisputed that the Hon'ble Designated Authority has complete discretion to include a domestic producer which is also an importer, this discretion must be moored on the touchstone of reasonableness and equity. Therefore, the inclusion of SI Group as domestic industry must be based on a rational and objective examination of facts.
- v. That in plethora of cases decided by the Authority in the past (Anti-dumping investigation concerning imports of 'Viscose Staple Fibre excluding Bamboo fibre' originating in or exported from China PR and Indonesia- 2010; Soda Ash originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Iran, Pakistan, Ukraine and USA- 2012; Mid-term Review (MTR) Anti-Dumping investigation concerning imports of 'Carbon Black used in rubber applications', originating in or exported from China PR, Australia, Russia and Thailand -2013, Electrical Insulators-2015, etc.) the issue has been decided by the Authority based on certain principles. In the light of the earlier precedents involving similar situations faced by the Authority, the key parameters typically examined by the Authority for exercising its discretion while excluding or including a domestic producer from the ambit of "domestic industry" are as follows:
 - a. Quantum of Imports in Comparison to Production and Sales;
 - b. The level or long term nature of the commitment shown by the producer to the domestic production, as opposed to importing activities;
 - c. If inclusion of a domestic producer would distort the injury findings, it must be excluded.
- vi. That by juxtaposing the above information on SI Group with the identified parameters for the Authority to exercise its discretion, the following relevant factors would emerge:
 - The imports made by SI Group account for a large share of not just production but also sales made by the domestic industry.
 - As is evident from the data that its imports from countries subject to anti-dumping duties/ongoing investigations are over 37% of the total production of SI Group.
 - Therefore, it is undisputed that SI Group has not just imported from sources of alleged dumping, but also benefitted from the alleged dumping and in the process shielded itself by partaking in the dumping activities.
 - The current activities of SI Group are merely a continuation of a long standing trend as also recognized in the previous investigations carried out by the Authority, whereby it is clear that SI Group has had a long commitment towards importing the product under consideration from sources of alleged dumping.
- vii. That the Authority may segregate and analyse the imports made by SI Group into duty paid and duty free imports and the impact thereto on its operations and margins, and make the same available for the interested parties so as to allow them to make meaningful submissions in this behalf.
- viii. That in light of the above, the Authority should exercise the wide discretion accorded to it under the Anti-dumping Rules in a judicious manner in consideration of the facts and evidence before it and exclude SI Group from the scope of the domestic industry for the purpose of the injury examination.

D.2 Views of the Petitioners

12. The petitioners, in their submissions, have argued that the petitioners in the present investigation namely, M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited and SI Group India Ltd, are the only producers of the product under consideration in the country. Although M/s. SI Group India Ltd has imported subject goods, these imports are not from the subject countries. Moreover, these imports have been made under duty exemption scheme for export production or after paying custom duty for captive consumption used for downstream products. The company hasn't imported for trading purposes and therefore, this behaviour should not be considered as causing injury to domestic industry. It has been further argued that since imports by SI Group pertain to non-subject countries, they are not relevant for present investigation.

13. It has been further argued that the Designated Authority, in various Acetone and Phenol cases, has held that whether imports are for captive consumption or commercial sales is an important distinction. However, notwithstanding the above should the Authority consider that SI Group cannot be a part of domestic industry the Authority can exclude SI Group from the scope of domestic industry and proceed on the data/information pertaining to M/s. HOCL alone.

D.3 Examination by the Authority

14. The Authority has examined the issue of eligibility of M/s. SI Group, to be treated as a part of the domestic industry for injury examination, in the light of the above arguments put forth by the interested parties, the extant Rules and the jurisprudence evolved on the issue.
15. The Authority notes that SI Group and HOCL filed a combined application for initiation of a combined sunset review investigation covering both the products as the domestic industry, countries involved and period of investigation were same for both the products. At the time of investigation SI Group claimed that they had imported certain quantities of Phenol during the proposed POI from various countries under duty exemption schemes for export production and certain quantities were imported, from various countries, including the countries under investigation, with payment of applicable duties for captive production of downstream products. The Company further declared that they imported certain quantities of Acetone under duty exemption schemes for export processing. It was declared that they have not sold any imported goods in the domestic market. Based on these declarations SI Group was included in the scope of the domestic industry at the time of initiation pending further inquiry into the issue.
16. During course of the investigation it has been found that during the POI SI Group imported 12246.43 MTs of Phenol out of which 7455.732 MTs were imported under duty exemption schemes for export production and remaining 4745.346 MTs were imported duty paid. Out of the duty paid imports 45.35 MTs were sold in the domestic market. It is further noted that all the imports are from countries attracting antidumping duty and 800 MTs have been imported from Thailand, which is one of the countries under investigation in this case. The imports of this Company are about 23% of its own production of Phenol during the POI. Similarly, SI Group imported 9924 MTs of Acetone under duty exemption schemes for export production. It is further noted that all the imports of Acetone are from countries attracting antidumping duty though no imports have been made from the countries under investigation. The imports of Acetone are about 30% of its own production during the POI.
17. The Authority further notes that in its submissions as recorded above the Company had argued that since imports by SI Group pertain to non-subject countries they are not relevant for present investigation. It has been further argued by the petitioners that SI Group did not import the goods for trading purposes and therefore, this behaviour should not be considered as causing injury to domestic industry, though the investigation reveals that about 45MTs of duty paid Phenol imported by this Company was sold in the market during the POI. Investigation also reveals that SI Group continues to import substantial volumes of both Phenol and Acetone during the post POI period of these two investigations. The past history of the Company also shows that they have been consistently importing the goods for their own consumption.
18. With this factual position of the case the Authority turns to the definition of the domestic industry and the discretion available to it under the extant Rules. Rule 2(b) of the Antidumping Rules provides as under:
2. (b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"
19. In the instant case one of the complaining domestic producers, i.e., SI Group, has been importing of both Acetone and Phenol for its captive consumption largely for export production. This fact was also before the Authority in the earlier investigations and this Company was included in the domestic industry in certain cases and in certain other cases it was excluded in the factual matrix of those cases. It is now established position of the law and jurisprudence evolved in other investigating authorities that Article 4.1 of ADA and Rule 2(b) of Antidumping Rules do not provide for the automatic exclusion of

producers which themselves import the dumped products, but rather obliges the Authority to examine, on a case-by-case basis, whether the inclusion or exclusion of any producer in such a situation is warranted. In deciding whether to exclude a domestic producer from the scope of the domestic industry, the Authorities generally examine the following factors:

- Whether the imports are sporadic and small compared to its own production and sales, not a regular phenomenon;
- Whether the imports are necessitated to tide over certain situations, say production issues; or supplementing the grades not manufactured by it; or quality testing and product development etc.;
- Need for completing their product range so as to be able to satisfy demand;
- Whether there is no other viable domestic producer to be defined as domestic industry.

20. The discretion available to the Authority under Rule 2 (b) has been used in the past with due circumspection, in situations where the complaining producer is the only domestic producer or the imports are not very significant in comparison to their production and sale and/or imports are meant for product development and testing etc. In the instant case, SI Group has been importing the subject goods in significant quantities though it has been submitted that major portion of the goods are being imported for its downstream production for export sales. Further, a small quantity of the imports has been sold in the domestic market and this fact was not brought to the notice of the Authority at the time of initiation. However, the Authority notes that there is only one other domestic producer in the country in the public sector i.e., M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd.(HOCL) with significant production capacities. But the production facilities of HOCL has been on and off out of production and operated only for few months during the POI because of certain other factors, though the domestic industry has argued that the production of this producer has been significantly affected by several factors, including prolonged dumping from various sources leading to closure of the plant for a considerable period during the POI. In this situation, if SI Group is disallowed to be a part of the domestic industry for the purpose of injury examination, there will be practically no viable domestic industry to evaluate the injury and injury investigation will be significantly skewed or would not enable a reasonable analysis of the impact or likely impact of the imports from the subject countries.

21. In view of the above situation, the Authority is inclined to use the discretions available to it under Rule 2(b) with due circumspection and considers SI Group as a part of the domestic industry for injury examination in this case.

22. The opposing interested parties, in their post disclosure submissions, have commented that the Authority has taken a step in the right direction by examining several factors in deciding whether to exclude a domestic producer from the scope of the domestic industry. However, In spite of analyzing the above factors, the Authority has decided to exercise its discretions available to it under Rule 2(b) with due circumspection and has determined that SI Group constitutes Domestic Industry, simply because if SI Group is disallowed to be a part of the domestic industry for the purpose of injury examination, there will be practically no viable domestic industry to evaluate the injury and injury investigation will be significantly skewed or would not enable a reasonable analysis of the impact or likely impact of the imports from the subject countries. This might set a perilous precedent, whereby the Indian manufacturer will always find a way to qualify as domestic industry despite importing the subject goods and benefitting out of such imports. It has been further argued that the imports made by SI Group have had a substantial impact on the domestic market in India, even if they were mostly utilized for downstream exports. Further, SI Group has evidently benefited from these imports since it is able to competitively price its downstream product in the export market.

23. In this connection the Authority notes that all issues raised by the opposing interested parties have been examined and in the factual matrix of the case it has been found necessary to retain SI Group as a part of the domestic industry for injury examination in this case.

E. Interested Parties to this investigation

24. Apart from the petitioners, the responding exporters and importers, who have made themselves known as interested parties in this investigation, as listed in para 5 (iv) and (vi) above, and the Governments of the responding countries have been treated as interested parties to this investigation.

F. Miscellaneous Submissions**F.1 Confidentiality**

25. The opposing interested parties, in their submissions, have contended that petitioners have claimed excessive confidentiality and production figures of Phenol in injury period and POI have not been provided while the same for Acetone have been provided in the petition. It has been argued that the domestic industry has not provided the basis for adjustments to export prices and Indexed ranges for costing information in Format A, B, C-1, C-2, D and E have not been provided and the underselling margin, capital employed and non-injurious price have not been disclosed in the petition in summarized form or in indexed ranges.
26. With regard to the confidentiality issues the domestic industry has submitted that all confidentiality claims of the domestic industry are as per the legal provisions, trade notice issued by the DGAD, and practice being followed by Authority in this regard. It has been further submitted that the questionnaire responses submitted by the interested parties are excessively confidential and prevent the domestic industry from making reasonable submissions.
27. The issues raised by the interested parties with regards to confidentiality have been examined. The Authority notes that to the extent possible and practicable the confidentiality claims of various parties submitting the information have been examined and confidentiality claims admitted on the basis of nature of information provided by the parties. As far as the submissions of the exporters are concerned, the information provided by the exporters, to the extent they are not business sensitive to the party providing the same, have been placed in the public file. In view of the above the objections of all parties with respect to confidentiality claims of the opposing parties have been disposed of.

F.2 Other Issues

28. The opposing interested parties have further argued that the Petition for sunset review filed by the Petitioners is deficient to the extent that it does not adequately address likelihood and provides baseless allegations without any evidence to corroborate its claims. In fact, as regards the claim of likelihood, the Petitioners appear to be contradicting themselves. The Petitioners have claimed in the petition that the performance of the domestic industry shows no improvement. In the same paragraph, the Petitioners have then stated that there is no injury to the domestic industry because dumping has continued at low level. Such ambiguous statements are meant to mislead the interested parties and the Designated Authority. Therefore, the petition should be rejected.
29. Further the Petitioners have out rightly contradicted themselves on their own Petition as far as imports of the subject goods from Japan. The data indicates that there has been no import of the subject goods from Japan in the period of investigation and the previous year.
30. It has been submitted that Authority has, in several investigations, examined such a factual scenario, wherein there were no present imports from the subject countries in the recent years and revoked the duties in such cases. Therefore, given the fact that: (i) there are no imports of the subject goods from Japan; and (iii) SI Group being major importer of Phenol during POI, there is no reason for continuing the anti-dumping duty in force on imports of the subject goods.
31. The exporters, in their submissions have also argued that the petitioners are inherently inefficient and have caused injury to themselves due to their operational infirmities and setbacks and resorting to repeatedly reliance on antidumping measures for over a decade. It has been argued that since its inception of its plant in 1987, HOCL has failed to make any improvement in its production facility or process even though the demand in the country has increased by nearly 200% since 1999. Since 2005 HOCL has been classified as a sick company and recently due to fall in international prices of crude Phenol manufacturing plant of HOCL has been shut down and HOCL has publicly admitted that these shutdowns are as a result of raw materials shortages which have no co-relation with the alleged dumping of the subject goods. Further, severe shortage of the working capital has also led to stoppage of production.

32. Apart from the above M/s. Century Ply board limited, in its brief submissions, has made the following submissions:
- That they are one of the major users of Phenol, which has been subjected to antidumping duties for a long time on the request of HOCL.
 - That HOCL has shut down its Phenol plant since August 2015 and since then HOCL has not been able to supply Phenol. Earlier also they were working intermittently.
 - That after shutdown of the plant, HOCL has issued tenders seeking bids for running the plant on toll contract basis. However, considering the condition of the plant and machinery no one is coming forward to participate in the tender.
 - On the other hand, the users of the subject goods are being unnecessarily burdened with antidumping duty on the imports. Therefore, there is no reason to continue with the duties.
 - That unjustified levy and collection of antidumping duties on the subject goods is causing unnecessary burden on the consumers and end users and is contributing to the slowdown of the economy.
33. The domestic industry in its submissions has argued that the significance and purpose of imposition of anti-dumping duties is that the domestic industry gets increased fair market opportunities to sell its materials at fair prices. The domestic industry in the present case did not get fair market opportunity with the imposition of anti-dumping duty. However, cessation of anti-dumping duty would result in continuation or recurrence of duty and consequent injury to the domestic industry.
34. In their post disclosure submissions, the opposing interested parties have submitted that the merits of the present investigation can be adequately analysed only if due consideration is given to the history of the AD duties. The Authority has taken a due note of this fact in the disclosure statement. It has been argued that Anti- Dumping duties have been repeatedly relied on by the domestic industry for over a decade to buffer its own inefficiency and have attempted to systematically eliminate all competition from the domestic market.
35. The Authority notes that this product has a long history of anti-dumping investigations and duties have been imposed on the import of the subject goods from various countries since 2002. Apart from the subject countries, the duties are currently in force against imports from Chinese Taipei, USA, EU, Korea RP, South Africa and Singapore.
36. With regard to the arguments of the interested parties that the petitioners are seeking repeated protection of antidumping duty while they are inherently inefficient, the Authority notes that in a sunset review investigation it is the consistent practice of the authority to review all the aspects of the original investigation, including the likelihood scenario of dumping and injury in the event of cessation of duties. Accordingly, all issues raised by the interested parties have been duly examined to the extent they are relevant and supported by evidence.
37. All other issues raised by the interested parties with regard to dumping and injury have been addressed in the respective sections in this finding to the extent they are relevant and supported by evidence.

G. Methodology of Determination of current Dumping

G.1 Legal Positions

38. Section 9A (5) of Customs Tariff Act, 1975 provides that: -

“The anti-dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti-dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.”

39. Accordingly, in a sunset review investigation the Authority is required to examine:

- Whether the dumping continues after imposition of the antidumping duty and if so, whether it is likely to continue;
- In cases where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti-dumping duties;
- Whether the domestic industry continued to suffer material injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are removed;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti-dumping duties.

40. Therefore, the Authority has first proceeded with the examination as to whether dumping of the subject goods continues from the subject countries and whether dumping is likely to continue or recur if the duties are revoked, before examining whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of such dumped imports and injury is likely to continue or recur in such a situation.

G.2. Examination of Continuation of Dumping: Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins.

41. The Authority notes that the following producers and exporters from Thailand and Japan have submitted their questionnaire responses:

1. M/s. PTT Phenol Company Limited, Thailand (Producer)
2. M/s. MITSUI CHEMICALS, INC., JAPAN (Producer)
3. M/s. MITSUI & CO., LTD., JAPAN, (Exporter)
4. M/s. MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD., Singapore (Exporter)

42. The current dumping and likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods from these two countries have been examined based on the information filed by the cooperating exporters and other information provided by the domestic industry as follows:

(a) Thailand

43. As per DGCI&S import data relied upon 34,308 MT of Phenol was imported from Thailand during the POI. M/s. PTT Phenol Company Limited, Thailand (PPCL), one of the major producers of the subject goods in Thailand, has filed its questionnaire response in this case. As per the verified data of this exporter, they had exported [***] MTs of the subject goods to India during this period. Considering the time lag between the exportation and importation, the data seems to match.

44. During the POI PPCL exported the subject goods to India directly as well as through unrelated exporters i.e., M/s. Mitsui & Co., Ltd., Japan and M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd., Singapore. These unrelated exporters have also filed their questionnaire responses. The responses filed have been verified through on-spot investigations. Accordingly, the normal value, export price and dumping margin have been determined based on the verified data of the producer and the exporters as follows:

Normal Value

45. During the POI PPCL sold [***] KG of the subject goods in the domestic market to unaffiliated customers, mostly on ex-works basis with few transactions on delivered basis, with various payment terms. It was noted that though the domestic sales were throughout the POI, the export sales were only in certain months in the POI. Due to significant fluctuation in prices of basic raw materials, i.e. benzene and propylene, in the global market the producer has requested for determination of normal values and export prices on monthly basis and has provided month-wise cost sheet of Phenol. Accordingly, the month-wise domestic sales were subjected to ordinary course of trade test and the monthly normal values have been determined as follows, after adjusting the domestic sales prices for expenses towards Inland Freight, Handling expenses and Credit Cost, wherever applicable, as given in the dumping margin table below.

Export Price

46. During the POI PPCL exported [***] Kg of the subject goods to India against [***] transactions to unrelated traders and end users. Out of this [***] Kgs were exported through the trading Company Mitsui and Co. Japan, which in turn exported the goods through its related company M/s. Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd., Singapore. Both these companies have filed their questionnaire responses. A small quantity (only one transaction) has been sold through another trading Co. in Hong Kong. Rest of the quantity has been sold to direct customers in India.
47. As far as exports through, M/s. Mitsui & Co., Limited (MBK) is concerned, MBK purchases goods from PPCL and sells to its associated Company, M/s. Mitsui & Co. Asia Pacific Singapore ("MAP"), which in turn sells the goods to various countries, including India. During the POI MBK exported [***] of the subject goods (Thai Origin) to India against [***] transactions through MAP. All transactions have been invoiced to MAP on FOB/CFR term with 90 days TT term and MAP has, in turn sold the goods to independent end users in India. Direct exports of PPCL were on Ex-works/FOB/CFR terms against LCs with various credit terms.
48. Phenol is first delivered to Thai Tank Terminal for distribution in bulk, both for domestic and export. The Company pays a fixed fee and throughput fee to Thai Tank Terminal. Accordingly, PPCL has claimed handling expenses, which are comprised of storage and throughput expenditure. The net ex-works export prices of the company for its direct exports as well as exports through the trading companies have been determined after due adjustments towards Inland freight, ocean freight, handling expenses, credit cost, bank charges and commission, wherever applicable. The exports are in bulk form and no packing expenses are involved. Accordingly, month-wise net ex-works export prices work out as given in the dumping margin table below.

Dumping margin: PPCL-MBK-MAP

49. The month-wise normal value determined at ex-works level have been compared with the month-wise net ex-works export price to arrive at the dumping margin for PPCL as follows:

Row Labels	Sum of Quantity in Kgs	NV US\$/Kg	EP US\$/Kg	DM US\$/Kg	DM %
Customer	***			***	0-5%
Apr-13	***	***	***	***	
May-13	***	***	***	***	
Aug-13	***	***	***	***	
Nov-13	***	***	***	***	
Feb-14	***	***	***	***	
Jun-14	***	***	***	***	
Aug-14	***	***	***	***	
Sep-14	***	***	***	***	
Trader	***	***	***	***	0-5%
Apr-13	***	***	***	***	
May-13	***	***	***	***	
Jul-13	***	***	***	***	
Aug-13	***	***	***	***	
Jan-14	***	***	***	***	
Feb-14	***	***	***	***	
Apr-14	***	***	***	***	
May-14	***	***	***	***	
Jun-14	***	***	***	***	
Jul-14	***	***	***	***	
Aug-14	***	***	***	***	
Sep-14	***	***	***	***	
Grand Total	***	***	***	***	0-5%

50. In its post disclosure comments the domestic industry has submitted that since the trader in Hong Kong who carried out a single transaction during the POI the channel of export is not complete and therefore, individual treatment should have been denied to PTT Phenol. The Authority notes that the exports of PTT through the Hong Kong trading company was a single transaction accounting for less than 5% of total exports to India and therefore, the determination has not been affected by absence of any significant data.

All other exporters from Thailand

51. The entire exports from Thailand during the POI have been accounted for by the exports made by PPCL. There is no other producer of the subject goods in Thailand. Therefore, determination of residual dumping margin for other producers and exporters in Thailand is infructuous and therefore, has not been carried out.

(b) Japan

52. The DGCI&S data relied upon indicates that no imports of the subject goods has taken place from Japan during the POI. Only a very small quantity of 48 MTs was imported during 2012-13 and thereafter there has been no imports. M/s. Mitsui Chemicals, Inc., Japan, one of the leading producers of the subject goods, has a filed a questionnaire response and has submitted that they have not exported the subject goods to India during the POI. Therefore, no determination of dumping margin has been made in respect of Japan.
53. The above examination indicates that the dumping margin of the subject goods imported from Thailand during the POI was marginally above *de minimis* level and there was no dumping from Japan during the said period.

H. Likelihood of continuation or recurrence of dumping

H.1 Views of the opposing interested parties

54. The opposing interested parties, in their submissions have argued that
- Petitioners have calculated a vague and unsubstantiated dumping margin.
 - Petitioners have not only not provided any evidence to substantiate export orientation; they have failed to give the source of third country data and evidence in this regard. They should be directed to submit the same.
 - The argument of price attractiveness is contradictory because the petitioner's data suggests that the present export price to India does not allow for recovery of cost. Petitioner's argument contradicts the concept of producer's equilibrium. They are posing selling below cost to be 'attractive'.
 - Price undercutting has remained constant in the POI yet the extent of injury and profitability has seen radical variation implying that price undercutting has no correlation to the injury suffered by the domestic industry.

H.2 Views of the domestic industry

55. The domestic industry, in its submissions has argued that
- The dumping has continued in case of Thailand. The volume of imports is significant enough in case of Thailand to allow a determination with regard to likelihood in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - In case of Japan, although there have been no imports during the present POI, the presence of, significant exports to third countries at dumped prices clearly shows likelihood of dumping and injury. Thus the dumping is likely to recur in case of cessation of anti-dumping duty.
 - There are significant exports from Japan to third countries revealing a significant injury margin. There is significant dumping in the third countries from Thailand as well. Therefore, in the event of cessation of the anti-dumping duties, there is strong likelihood of these third country imports getting dumped in India.
 - Dumping Margin determined in previous investigations and present petition are significant and clearly shows likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti-dumping duty.

- v. The prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which the goods are being sold in the domestic market.
 - vi. There is significant price undercutting which is likely to intensify if the duties are revoked. Significant price undercutting by the Japanese exports is likely, considering the prices at which the Japanese exporters have exported the product under consideration to third countries in the POI.
 - vii. There is no contradiction in domestic industry's statements with regard to likelihood. Dumping of the product under consideration, injury to the domestic industry, injury to the domestic industry from present subject countries, injury to the domestic industry from other dumping sources, injury to the domestic industry from present subject countries in the event of cessation of anti-dumping duty are all different parameters and must be considered accordingly.
 - viii. Excess capacity is a proved parameter to determine likelihood, it is sufficient to show high probability of injury to the domestic industry.
 - ix. Excess capacity in a country can lead to many problems in the home country such as falling product prices, deteriorating profitability, corporate –sector distress and financial sector distress which can cause the producer to look for avenues outside the country at disposable prices. The purchasing power of the citizens may not grow at the same rate. In such situations since the demand is already excessive, the investments are controlled because in such a scenario investments result in loss rather than profit. A glut of capacity is an important indicator of likelihood analysis in anti-dumping investigations.
 - x. It is not necessary that the price undercutting increases with increase in losses. The two are different parameters.
56. In their respective post disclosure submissions, the domestic industry and the opposing interested parties, have reiterated their positions with regards to the likelihood of continuation or recurrence of dumping.

H.3 Examination by the Authority

57. It was noted in the previous section that there were no dumped imports from Japan during the POI. The dumping margin of the imports from Thailand is marginally above the *de minimis* level. In view of the above, what is required to be examined in this review is whether the dumping would continue or recur if the duties are revoked. In this connection the Authority has looked at the price behavior and capacities of the major producers in the subject countries.
58. As far as Thailand is concerned, PPCL is the only producer of the subject goods in Thailand with a capacity of about [***] KT per annum which they operate at above 100% capacity utilization. The data submitted by PPCL indicates that while their domestic sales and captive transfers over the injury investigation period has increased exports show a declining trend. It has been brought to the notice of the Authority that PPCL is considering capacity addition of about [***] KTA in the near future to double its phenol capacity for the purpose of fulfilling major demand from domestic market and third countries. In Thailand, current demand of phenol is approximately 330,000 MT per annum, mainly for BPA production. There are only two BPA producers in Thailand namely, PPCL and Bayer Thai Company Limited who consume more than 90% of demand of Phenol. Export quantity of Phenol from PPCL has been significantly decreased since December 2010, after PPCL started to captively consume Phenol for its own Bis-Phenol-A (BPA) production, mainly exported to China. The new Plant is to cater to this growing domestic demand. With Bayer Thai consumption, total domestic consumption of phenol in Thailand will be about [***] KTA and only about [***] KTA will be available for exports. However, PPCL has submitted that they already have significant committed/contracted quantities for Korea, Taiwan, China, South-East Asia markets for this spare capacity. Therefore, it appears that PPCL will not have significant spare capacity to significantly increase the volume of exports to India in the near future.
59. The price trend of PPCL during the period of investigation indicates that the prices in the domestic market, exports to India and third countries were in a narrow band. The actual margin of dumping established in the previous section is marginally above *de minimis* level. Hence, the argument that the third country exports from Thailand are at dumped prices and therefore, there is a likelihood of intensified recurrence of dumping to India, if duties are revoked, do not seem to be valid. In this connection the post POI (Oct 2014-March 2015) data has also been examined and the data shows that

total import, as well as import from Thailand, has increased apparently because HOCL has gone completely out of production and the additional gap of about 40,000 MT has to be filled up through increased imports. On the price front the prices from across the countries show significant drop from the first quarter of 2015 apparently because of crude price situation. Therefore, it appears that the imports from Thailand would continue at the current level even if the duties are removed. Since the prices from Thailand is following the global trend, major reduction of prices by this producer *vis a vis* other global producers do not appear to be imminent.

60. As regards Japan, there is no imports from that country during the POI and also during the post POI period. During the injury investigation period there was some import in 2011-12 and a very small quantity of 45 MTs was imported in 2012-13. As per the information submitted by the interested parties the total production of Phenol in Japan is roughly 775KT/p.a. against an Annual demand of roughly 600KT/p.a. Mitsui chemicals, one of the major producers in Japan, having annual production about [***] KT, in its response, has indicated that it is already producing about [***] KT per annum indicating thereby that it has no spare capacity. Its annual sales are about [***] KT, rest being captive consumption. As per the submissions of MCI [***] % of its sales are dedicated for captive consumption and domestic sales and rest being for exports. Its exports have significantly declined to about [***] KT/p.a. In its response the company has intimated that it closed its joint venture plant with Idemitsu Kosan in September 2014 indicating further reduction in its capacity.
61. The price level indicated by MCI shows that at gross level domestic prices are higher compared to the export prices though the exports are very small compared to domestic sales. There was no export to India during the POI apparently because of high antidumping duty on Japan. There is no import from Japan in the post POI period either. Therefore, there is a possibility of some volume of imports from Japan entering the Indian market at dumped prices, if the duties are removed. But likelihood of significantly high imports appears to be low keeping in view the demand supply position in that country.
62. Considering all the above the Authority is of the view that though imports from Thailand may continue at the present level, and some imports may take place from Japan, if the duties are revoked, there is no imminent likelihood of recurrence of intensified dumping of the subject goods from the subject countries if the duties are revoked.

I. Methodology and Determination of Injury and Causal Link

63. As noted earlier, in a sunset review investigation, with regard to injury examination, the Authority is required to examine:
 - Whether the domestic industry continued to suffer injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue;
 - In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti-dumping duties.
64. Therefore, the Authority has first examined whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject countries before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties from the subject countries. Examination of material injury to the domestic industry is in accordance with the Article 3 of the AD Agreement and Annexure II to the AD Rules, 1995.

J. Determination of Injury and Causal Link

J.1 Submissions of the opposing interested parties

65. The opposing interested parties have made the following submissions with regard to the injury and causal link:
 - i. That there is a contradiction in the petitioners' submissions that domestic industry performance shows no improvement and at the same time domestic industry claims that this is a case where dumping has continued at low level and the domestic industry has not suffered injury because of low level of dumping but injury to the domestic industry is likely in case the present anti-dumping duties are withdrawn.

- ii. That as per market intelligence it is known that a large portion of the imports of the subject goods have been made in the injury period as well as the period of investigation under the advance license scheme. Under the said scheme, any domestic producers seeking to export his finished products may import their raw materials under the said advance license. The advantage of such a scheme would be that any imports made under advance license are exempted from any anti-dumping or safeguard duties. SI Group, one of the applicants in this case, has imported significant quantities of the subject goods under advance licence. Therefore, DA must segregate and analyze SI Group imports into duty paid and duty free imports and the same should be made available to the interested parties;
- iii. Citing the judgment in *Vetcare Organic Pvt. Ltd. vs CESTAT, Chennai*, 2011 (269) E.L.T. 444 (Mad.), and *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. vs. Designated Authority*, 2010 (253) E.L.T. 564 (Tri. - Del.), the opposing interested parties have argued that imports under advance license ought to be identified and excluded from the import volumes considered for examining injury and dumping.
- iv. That any injury suffered by HOCL is inflicted by its own inefficiencies, operational infirmities and other setbacks and has been seeking protection of antidumping law for over a decade now which is evident from the plethora of investigation since 2002.
- v. That in a Safeguard investigation in 1999 HOCL submitted an adjustment plan in lieu of the safeguards duty in which they gave some exaggerated plans to expand capacity and minimise cost as they admitted then that one of the reasons identified by them is the lack of economies of scales. Despite that admitted fact and adjustment plans HOCL's capacity remains at the same exact level as it was in 1999.
- vi. That in the present petition HOCL has admitted that the long shutdowns are a result of raw material shortages, and other issues which have no correlation to the alleged dumping of the subject goods. Despite several help from parent ministry and various anti-dumping duties HOCL was classified as a sick company by BIFR under SICA and has remained so for nearly a decade. Reliance has been placed on the Ninth Report of Parliamentary Committee on Public Undertakings (2015-16) which clearly records that even after 16 years having elapsed from its proposal submitted to Directorate General of Safeguards, HOCL has not upgraded the technology for manufacture of Cumene by the use of modern zeolite catalyst system.
- vii. That this shows that there is indeed no injury due to the alleged dumping and the Petitioners are abusing the anti-dumping laws by misrepresenting before the Hon'ble Authority. Further, this reflects an inability to overcome HOCL's inefficiency and a lack of initiative to expand and seize the expanding demand.
- viii. That HOCL, has had repeated and sustained plant shutdowns in recent years, including the period of investigation. Since 2005, HOCL has been classified as a sick company under the Indian law. Recently due to an international fall in crude prices, the Phenol manufacturing plant of HOCL was shut down again. These continuous shutdowns have impacted the ability of HOCL to supply to the domestic market and consequently HOCL's performance has suffered. In fact, HOCL has publically admitted that these shutdowns are as a result of raw material shortages, which has no correlation to the alleged dumping of the subject goods.
- ix. That has admitted by HOCL, the Rasayani plant remains closed as of today and yet the Petitioners claim that their production and sales levels have been falling due to alleged dumping.
- x. That a severe shortage of working capital has also led to stoppage in production. The Company is on record in public domain that Kochi Refinery, which was supplying the raw materials, has refused to continue the supply as the Company had a debt of over 90 crores. Therefore, reintroduction of the anti-dumping duty will hardly help them to bring the plant to operation.
- xi. That there is a huge demand-supply gap in the country making imports inevitable.
- xii. That the injury to the domestic industry is not due to imports but due to various other factors as highlighted in the Parliamentary Committee Report such as high cost of production, huge demand-supply gap, poor technology, plant inefficiencies, plant shutdowns, lack of foresight and poor management.

- xiii. The production has suffered due to recurring and sustained plant shutdowns. The domestic industry has lost 22% market share while the subject countries imports have gained only 4% of the market share. The majority share is attributed to the imports from Korea and Singapore.
- xiv. The performance of SI Group, the only other producer of the subject goods in India has been much better, indicating internal inefficiencies of HOCL causing loss of market share.
- xv. That excess capacity of the exporters cannot be prejudiced against them. There is no proposition under any law or WTO that one must only produce what is required by it. The assumption that any excess capacity in the world will hit only India is faulty and hurts the consumers.
- xvi. That there is breach in causal link as no injury has been suffered on account of subject imports. There is heavy impact of imports from Korea and other countries not including subject countries. HOCL has acknowledged that it is the withdrawal of anti-dumping duties on other countries and not the subject countries, since the duties on subject countries were never ever removed.

J.2 Submissions by the domestic industry

66. The domestic industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:
- i. That the demand for the product under consideration has increased in the POI with respect to the base year.
 - ii. That the volume of imports from Thailand increased in 2011-12, declined in 2012-13 and increased thereafter till POI. Further imports in the POI were much higher than the imports in 2010-11 and significant enough to establish dumping and injury margin for the purpose of deciding the likely situation.
 - iii. As regards Japan, while there were no imports in the present period, Japan has exported significant volumes to third countries, which shows significant price undercutting, dumping margin and injury margin in the event of cessation of anti-dumping duty and diversion of these goods to India. There is strong likelihood that volume of imports shall increase further if anti-dumping duties are removed.
 - iv. In case of Thailand the subject imports are undercutting the prices of like product in India. However, in case of Japan third country exports are at such prices that cessation of anti-dumping duty shall result in diversion of goods to the Indian market and the domestic industry would suffer price undercutting.
 - v. Imports are undercutting the domestic price and effect of cessation of anti-dumping duty shall have significant suppressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
 - vi. While the current low volume of imports from Thailand and no imports from Japan was due to no anti-dumping duty on other countries (and thus an option with the consumers to source from alternative sources), should the present anti-dumping duty be withdrawn, it is evident that the dumping and consequent injury to the domestic industry would intensify and the imports from these countries shall cause injury to the domestic industry.
 - vii. Domestic industry has continued to suffer material injury due to continued dumping of the products in the country.
 - viii. The jurisprudence on the issue of advance licensing warrants that the import volume coming under advance licensing is causing a price injury. Therefore, it cannot be excluded.
 - ix. The imports of SI Group are majorly duty free imports made against export obligation and therefore, are not a cause of concern for the present investigation.
 - x. There is no obligation on the Designated Authority to segregate and analyze SI Group imports into duty paid and duty free imports.
 - xi. Demand supply gap justifies imports per se but not dumping of the product in the country. As held by CESTAT in the matter of DSM Idemitsu, if the exporters wanted to supply the goods to meet the requirement in Indian market that could be done by exporting the requirements at a price equivalent to normal value but not at a dumped value and to capture the market.

- xii. In past anti-dumping duties have only been imposed when the parameters are satisfied.
- xiii. The claimed injury is not due to developments in technology. Further it is an established principle that domestic industry should be seen as it is and not in the context of ideal conditions.
- xiv. Even if HOCL was classified as a sick industry an analysis must be done as to whether it was a sick company due to other reasons without attributing injury caused by other factors to dumping.
- xv. Raw material shortages are a result of prolonged dumping and consequent injury. There is a direct causal link
- xvi. Dumping leads to injury, leading to decline in profitability resulting in losses suffered by domestic industry which impacts cash flow, which in turn affects the ability of the company to source raw materials. This leads to production suffering, which adversely impacts the capacity utilization and sales. As a result, cost of production increases due to lower production and losses further impact the cash flow. The mounting cash flows impact the ability of company to source raw materials and this cycle continues so long as the market remains impacted by dumping.
- xvii. With regard to SI Group interested parties have focused on difference in performance whereas the requirement under the law is deterioration (or likelihood of deterioration) in performance.
- xviii. Injury to the domestic industry from other dumped imports does not imply "no injury or likelihood thereof" from present sources.
- xix. That the interested parties referred to reviews/recommendations of the Parliamentary Committee on public undertaking at the time of oral hearing and read extensively about the contents of its report, projecting as if the Parliamentary Committee has actually found entirely different reasons for adverse performance of HOCL and that HOCL has wrongly attributed their difficulties to the dumping in their product.
- xx. Despite anti-dumping duties in the past many years the domestic industry has been suffering from unfair competition from one source to another. This is primarily due to significant surplus in the global market and the ability of the global producers to dump the goods. The suspension of production by HOCL may turn to complete shut down if domestic industry is not meted out justified anti-dumping duties.
- xxi. If there is any mismanagement at the end of HOCL then it is rightly being dealt with by the parliamentary committee since HOCL is a public sector undertaking. Further for the purposes of anti-dumping the Authority would only recommend duty after following requirements prescribed under the laws. Such a finding of the Committee in no way jeopardizes the investigation process of Designated Authority.
- xxii. Contrary to the averment of the opposing interested parties the Committee recognized the 'negative' impact of the withdrawal of anti-dumping duty as one of the significant factors leading to dismal situation of HOCL.
- xxiii. That dumping has not just impacted HOCL, SI Group has also suffered. The Designated Authority may kindly examine the injury statements of the two companies.

J.3 Post disclosure submissions of the interested parties

67. In its post disclosure submissions, the domestic industry, has mostly reiterated its stand on the injury and causal links and had inter alia submitted as follows:
- i. That the Price Undercutting is positive and is likely to increase the demand for the product under consideration in the market in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - ii. That HOCL suspended production because of intensified dumping of the product which has made its current operations totally unviable. HOCL has not completely gone out of business. It has merely suspended production. Which has been recommenced and a certificate as asked by the Authority was also provided
 - iii. That performance of the domestic industry in terms of production, capacity utilization, domestic sales, market share, profits, return on investments, cash flow has deteriorated. The information filed by SI Group clearly shows significant deterioration in its profits, cash flows and return on investment. While SI Group is a private enterprise, HOCL is a public sector organization. The financial losses being suffered by the company forced the company to reduce its production.

- iv. That sales realization has been below cost of production in the period of investigation.
 - v. That because of dumping of the global surplus of the product in the Indian market, HOCL could not improve its performance further and is once again suffering losses.
 - vi. That the domestic industry is still suffering continued injury from the imports of dumped subject goods;
 - vii. That even at best capacity utilization, HOCL would have suffered significant adverse price effect in the POI.
 - viii. That none of the factors such as exchange volatility, inflation, high interest rates, and volatile stock markets are responsible for claimed injury to the domestic industry. There has been no significant change on any of these factors and as far as domestic industry and the present product is concerned. The performance of the domestic industry has, however, significantly deteriorated which clearly establishes that such deterioration is not because of the other factors.
 - ix. That imports from Thailand are significant, which clearly shows that the Thailand producers are likely to cause significant injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty.
 - x. That HOCL has not adopted different methodology to allocate cost to Phenol and Acetone. HOCL has provided information in a consistent manner.
 - xi. That relevant parameters show that injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports and thereby establish causal link.
 - xii. That contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.
 - xiii. That pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.
 - xiv. That there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
 - xv. That technology for production of the product has not undergone any change nor are there any likely changes in coming future. Developments in technology are therefore, not a factor of injury.
 - xvi. That the fact of dumping is established by the Authority in all past cases. The significant global surplus in Phenol and Acetone capacity is clearly the cause of dumping of the product in India. Such significant surpluses are likely to continue. In fact, demand for Phenol is likely to increase without proportionate increase in demand of Acetone, which will further create pressure on Acetone prices in the global market.
68. The opposing interested parties, in their post disclosure submissions, have argued as under:
- That if import volumes (or prices) prevalent in advance license imports are injuring a domestic industry, any levy of anti-dumping duties will not remedy such an injury. Unless there is a wide policy change, no levy of anti-dumping duties will be able to protect the petitioners from advance license imports (whether dumped or not).
 - That imports might have been triggered due to the suspension of production by the domestic industry during the POI. Inflow of imports into India does not point towards dumping especially in the present case where the domestic industry has suspended production during the POI – in fact such competition is merely an indicator of a free market. Furthermore, as noted by the Authority at paragraph 71 of the Phenol disclosure statement, the major gain had been for the other non-subject countries attracting duties, and not subject countries. This aspect clearly indicates that there was no volume injury from the subject countries.
 - That the net sales realisation of the Domestic Industry still remains above the non-injurious price in spite of the fact that the cost and prices were affected due to suspension of the production by HOCL for a major part of the POI. This statement clearly indicates that there is a clear breach in causal link between imports from subject countries and the alleged injury claimed by the

Domestic Industry as the alleged dumped imports do not seem to restrict the Domestic Industry to recover its Non Injurious Price from the Indian market. Owing to this finding alone, the Authority should return a final finding recommending discontinuation of duties from the subject countries.

- That SI Group was in full production during the POI and was able to sell at a relatively higher price in the same market during the same period, much above the landed prices, which indicates that the dumped imports did not have suppression or depression effect on the domestic prices.
- That the HOCL shutdown was because of internal factors such as lack of modernization of technology, working capital crunch and non-supply of raw materials by the refinery due to mounting dues from HOCL and not because of alleged dumping from the subject countries.

J.4 Examination by the Authority

69. The Authority has taken note of various submissions of the interested parties and the domestic industry on the injury and causal links and all the averments made have been examined taking into account the facts available on record and applicable law. Accordingly, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence injury on account of imports from the subject countries in the event of cessation of the duties.
70. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...." In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
71. For the purpose of current injury analysis, the Authority is required to examine the volume and price effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry and its effect on the prices and profitability, to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.
72. The Authority notes that the application for continuation of antidumping duty was initially filed by HOCL and SI Industries and they have been treated as the domestic industry for the purpose of injury investigation in this review. However, as argued by the domestic industry performance of both the producers have been has also been examined separately, to the extent feasible, to see the state of health of both the domestic producers as HOCL was out of production for a considerable period during the POI thereby significantly affecting their performance indices.
73. The volume and price impacts of the dumped imports on the physical parameters of the domestic industry have been examined before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties.

A. Volume impact of dumped imports

(i) Import Volumes & share in Imports

74. The import data obtained from DGCI&S has been examined to analyse the trend in import volumes and prices and their impact on the domestic industry as follows:

SN	Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
1	Subject Countries	MT	12,047	23,140	5,594	22,872	34,308
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>192</i>	<i>46</i>	<i>190</i>	<i>285</i>
a	Japan	MT	0	1,079	48	0	0
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b	Thailand	MT	12,047	22,061	5,546	22,872	34,308
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>183</i>	<i>46</i>	<i>190</i>	<i>285</i>

3	Countries Attracting ADD	MT	87,580	1,09,181	1,61,481	1,56,774	2,35,162
	<i>Trend</i>		<i>100</i>	<i>125</i>	<i>184</i>	<i>179</i>	<i>269</i>
a	EU	MT	10,608	8,251	104	14,319	21,479
b	Korea	MT	3,425	872	15,533	49,741	74,611
c	Singapore	MT	1,146	897	498	24,776	37,164
d	South Africa	MT	11,223	10,494	14,033	18,604	27,906
e	Taiwan	MT	14,607	38,066	44,861	26,747	40,120
f	U S A	MT	46,571	50,602	86,451	22,587	33,881
4	Other Countries	MT	18,909	10,720	1,574	5,670	8,505
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>57</i>	<i>8</i>	<i>30</i>	<i>45</i>
5	Total	MT	1,18,536	1,43,042	1,68,649	1,85,316	2,77,974
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>121</i>	<i>142</i>	<i>156</i>	<i>235</i>

75. The data above shows that total imports during the injury investigation period grew almost by about 56% on annualised basis compared to the base year. However, while there is no import from Japan during major part of the injury period, including POI, imports from Thailand has increased significantly during this period by about 90% on annualised basis and account for about 12% of total imports. The Authority notes that though the subject goods are attracting antidumping duty on imports from several countries, some of the major exporters in Korea RP and Singapore are outside the ambit of the duty because of negative or *de minimis* margins. Therefore, imports from these countries have significantly increased during this period and account for about 85% of total imports, whereas imports from other countries have declined.

76. The interested parties have argued that a significant volume of imports are under advance licence scheme without payment of the antidumping duties and therefore, the imports should be segregated and analysed for the injury analysis. However, none of the interested parties has provided any information on the volume of imports under advance licence.

ii) **Assessment of Demand and Market Shares**

77. The interested parties have argued that there is a huge demand supply gap in the domestic market. The demand data determined as the sum of domestic sales of the Indian producers and imports from all sources is as follows:

SN	Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
	Demand in India						
1	Sales of Domestic Producers	MT	77,521	60,189	54,316	37,830	56,745
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>78</i>	<i>70</i>	<i>49</i>	<i>73</i>
	<i>HOCL</i>	<i>MT</i>	***	***	***	***	***
	<i>SI Group</i>	<i>MT</i>	***	***	***	***	***
2	Total Imports	MT	89,465	1,07,231	1,35,453	1,63,517	2,45,275
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>151</i>	<i>183</i>	<i>274</i>
3	Demand in India	MT	1,96,057	2,03,231	2,22,965	2,23,146	3,34,719
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>171</i>

78. The above data indicates that while demand has remained flat for last couple of years the imports have increased and domestic sales have declined significantly particularly during the POI, largely because of decline in HOCL's sales. The trend in market share of various players in the domestic market during the POI was as follows:

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Sales of Domestic producers	%	40%	30%	24%	17%	17%
HOCL	%	***	***	***	***	***
SI Group	%	***	***	***	***	***
Dumped Imports from subject countries	%	6%	11%	3%	10%	10%
Countries Attracting ADD	%	45%	54%	72%	70%	70%
Other Countries	%	10%	5%	1%	3%	3%
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%

79. The above data indicates that the share of the domestic producers in the total demand has fallen largely due to production loss of HOCL as the other producer is producing at almost its full capacity. The share of imports from Thailand has increased after a decline in 2012-13. But major gain has been for the countries attracting duties, which corner about 70% of the market demand in the country.

B. Price impact of dumped imports

i) Trend of Import Prices

80. The import prices of the subject goods imported from various countries during the POI as per DGCIS data is as follows:

Country	Price (Rs./Kg)				
	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Subject Countries	82	77	83	91	91
Japan	-	74	95	-	-
Thailand	82	77	83	91	91
Countries Already Attracting Duty	74	74	80	88	88
Eu	73	85	59	88	88
Korea Rp	74	86	86	91	91
Singapore	82	94	90	83	83
South Africa	67	69	71	81	81
Taiwan	80	78	81	92	92
U S A	74	69	80	87	87
Others	77	84	78	92	92
Grand Total	75	75	80	88	88

81. The data above indicates that the CIF prices of imports from all countries moved in a very narrow band during the POI except for South Africa and Singapore, where the prices were lower during the POI.

ii) Price undercutting effect of dumped imports

82. To examine the price undercutting effects of the dumped imports from the subject countries the landed values of the imports have been compared with the net sales realisations of the domestic industry.

Particulars	UOM	Japan	Thailand
Landed price of dumped imports	Rs./MT	No Imports	1,01,241
Net Sales Realization	Rs./MT		***
Price Undercutting (without ADD)	Rs./MT		***
	%		0-10%
Price Undercutting (with ADD)	Rs./MT		***
	%		0-10%

83. The data indicates that the dumped imports from Thailand marginally undercut the selling prices of the domestic industry.

(iii) Price underselling effects of dumped imports

84. The landed value of the dumped imports has also been compared with the Non-injurious price determined for the domestic industry taking into account the cost of production of both HOCL and SI Group to see if the dumped imports had significant price underselling effect on the domestic prices.

Particulars	UOM	Japan	Thailand
Non Injurious Price	Rs./MT	***	***
Landed Price of dumped imports	Rs./MT	No Imports	1,01,241
Price Underselling without ADD	Rs./MT		***
	%		0-10%
Price Underselling with ADD	Rs./MT		***
	%		0-10%

85. The above data indicates that the dumped imports had a very marginal underselling effect on the domestic industry's prices. However, net sales realisation remain above the non-injurious price in spite of the fact that the cost and prices were affected due to suspension of the production by HOCL for a major part of the POI.

(iv) Price suppression or depression

86. Since the cost of the domestic industry has been significantly affected by production loss and very low capacity utilisation of one of the producers during the POI, a reasonable analysis of the trends, to see if the price of the domestic industry has been considerably suppressed because of the presence of dumped imports, has not been possible. However, comparison of the non-injurious price, which is an indicator of the costs, and the landed value of the imports and sales realisation indicates that the prices are not suppressed. Moreover, the other domestic producer was able to sell at a relatively higher price in the same market during the same period, much above the landed prices, which indicates that the dumped imports did not have suppression or depression effect on the domestic prices.

C. Economic Parameters affecting Domestic Industry

87. The various physical performance parameters relating to the domestic industry are as follows:

(i) Actual and potential impact on Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

88. Considering the fact that the production the domestic industry (HOCL) was significantly affected during the POI, performance of both the domestic producer has also been examined separately in respect of sales, capacity, production and capacity utilization are as under, to see if the performance of both the producers was impacted by the dumped imports.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Capacity DI	MT	74,200	74,200	76,750	63,417	95,125
Trend		100	100	103	85	128
HOCL	MT	40,000	40,000	40,000	40000	60,000
SI Group	MT	34,200	34,200	36,750	36,750	55,125
Production DI	MT	80,796	67,500	59,921	43,537	65,306
Trend		100	100	89	64	97
HOCL	MT	***	***	***	***	***
SI Group	MT	***	***	***	***	***
Capacity Utilisation DI		109%	91%	78%	69%	69%
Trend		100	100	86	75	75
HOCL	%	***	***	***	***	***
SI Group	%	***	***	***	***	***
Domestic Sales DI	MT	77,521	60,189	54,316	37,830	56,745
Trend		100	100	90	63	94
HOCL	MT	***	***	***	***	***
SI	MT	***	***	***	***	***
Captive Sales	MT	2,499	5,942	6,870	6,525	9,787
Trend		100	100	116	110	165
HOCL	MT	***	***	***	***	***
SI	MT	***	***	***	***	***

89. The Authority notes that while SI Group was operating almost at its full capacity during the entire injury investigation period, HOCL's production has significantly declined since 2011-12. The Authority further notes that the production facility of HOCL was operational only for 119 days during the POI leading to this production loss and low capacity utilisation during the POI.

90. The interested parties have argued that the performance of the HOCL has been affected for a long time due to several internal factors. The petitioners on the other hand have argued that the performance has been affected because of presence of dumped imports from several sources. However, Authority notes that duties were in force on most of the major supplying countries, including the subject countries, during the entire injury period, except few producers from some of the countries. Moreover, near full capacity production of the other domestic producer does not appear to support this argument of the domestic industry, though certain fluctuation in international prices could have affected the production and capacity utilisation as is observed in the case of SI Group also.

(ii) Actual and potential impact on profit/loss, return on investment and cash flow

91. The financial performance of HOCL during the injury investigation period for the subject goods as shown in table below :

Profit/ Loss - Domestic	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI Annualised	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	100	114	129	129
HOCL	Rs/MT	***	***	***	***	***
SI	Rs/MT	***	***	***	***	***
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Trend		100	100	104	117	117
HOCL	Rs./MT	***	***	***	***	***
SI	Rs./MT	***	***	***	***	***
Profit/ Loss	Rs/MT	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend		100	100	-215	-294	-294
HOCL	Rs/MT	***	***	(***)	(***)	(***)
SI	Rs/MT	***	***	(***)	***	***
Return on Capital Employed	%	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend		100	100	-150	-108	-163
HOCL	%	***	***	(***)	(***)	(***)
SI	%	***	***	(***)	***	***

92. The Authority notes that the plant of HOCL was in operation for only 119 days out of 18 months of POI. Therefore, the cost is significantly affected by prolonged shutdown of the plant and would not reflect the true cost of production. The data of the previous years show that HOCL was an efficient producer of the subject goods with higher profit margins compared to its domestic competitors till the time it was using its capacity fully. HOCL's capacity utilization started falling since 2011-12 leading to reduction in margins and subsequent losses in 2012-13 onwards. At the same time the other domestic producer continues to have a positive profit margin throughout except 2012-13 when it faced a marginal decline in capacity utilization. It is clear that the losses suffered by HOCL are on account of its inability to produce and sale during the period under consideration. Therefore, it is important to analyze the reasons for the production loss during the injury investigation.

93. Since one of the domestic producer, i.e., HOCL's plant was not operational for a prolonged period due to various reasons other mandatory parameters are irrelevant in this scenario and have not been examined.

K. Overall Assessment of Injury and Causal Link

94. Examination of the injury parameters as above indicates that one of the domestic producers, i.e., HOCL has suffered significant production loss leading to financial losses. The previous section has established that there was no import from Japan. The imports from Thailand were at dumped prices but the dumping margins are marginally above the *de minimis* level. The other domestic producer continues to produce almost at full capacity and earn positive profit margins. Under these circumstances it is essential to examine whether the production loss and consequent financial losses suffered is on account of dumped imports from the subject countries or because of other factors.

95. With regard to the production loss of HOCL and consequent injury in terms of financial losses the opposing interested parties, quoting the Parliamentary Committee Reports and other publicly available information, have argued that the production unit of HOCL has been shut down because of its internal inefficiencies and management problems rather than dumping. It has been submitted that inability of the unit to modernize and scale up to economic size and working capital unavailability has led to shutdown of the plant and not because of the imports from the subject countries.

96. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has argued that HOCL suspended its production during the POI as the production and sales were unviable due to dumped imports and the plant has not been completely shut down. It has further been submitted that HOCL has resumed its production recently with certain arrangements of raw material supply from the Cochin refinery.
 97. The Authority notes that the production unit of HOCL was set up in late 1980s with a capacity of about 40,000 MTs of Phenol and 45000 MTS of Acetone and other ancillary products with raw material linkage with Cochin Refinery. The capacity and technology was perhaps based on the demand scenario and technology available at that point of time. Thereafter, the demand has increased significantly and technology has also improved, as noted by the Parliamentary Committee in its reports and submissions of the Company before other Authorities. But the Company has not been able to scale up the capacity or modernize the plant due to various reasons. The inability of the plant to scale up and modernize, coupled with dumping from several countries affected the performance of the Company and antidumping duties were imposed on imports of Phenol and Acetone from several countries starting in the year 2002. However, due to continued losses HOCL was declared a sick unit in 2005 and still continues to be under BIFR.
 98. The Rashayani unit of the Company engaged in several other products with a significant workforce has been shut down since 2013. The Cochi Unit, which produced Phenol and Acetone with certain other products, was however, producing with full capacity for certain period before this also got affected by working capital problems as the profits of this unit was supporting the fixed expenses of the other unit closed earlier. Due to mounting dues of over 90 Crores to Cochin Refinery, against supply of raw materials, the Refinery has stopped raw material supply to the unit leading to suspension of production of the Cochi plant since Mid-2015.
 99. The Authority further notes that imports from all major sources were attracting antidumping duties, except certain sources which were found not to be dumping in the respective investigations. Therefore, those imports cannot be attributed to the injury suffered by this producer.
 100. The interested parties have also raised the issue of lack of modernization and adoption of efficient production methods and scaling up of the capacities to economic size as noted in various reports and its commitments to other Authorities as one of the causes of the injury. The Authority notes that the production facilities of the Company are old and has not gone through major modernization due to various factors, including dumping from several sources.
 101. Therefore, overall assessment of the state of affairs of HOCL indicates that the closure of the plant is directly linked to its working capital and management issues rather than the dumped imports from the subject countries as antidumping duty protection was available against these imports for the entire injury investigation period. In view of the above the performance of the Company during the POI cannot be attributed to the imports from the subject countries. The very fact that HOCL has attempted resumption of production with certain agreements for raw material supply with Cochin Refinery further indicates that the suspension of production was due to raw material and working capital related issues and not significantly because of dumped imports from the subject countries.
 102. The performance of the other domestic producer i.e., SI Group does not show any significant deterioration. Their production, capacity utilization and sales remain stable and the profitability remains closer to their 2011-12 level. The performance of this company does not appear to be significantly affected during this period though substantial imports are taking place from several countries at similar price bands.
 103. Therefore, the Authority does not find any significant causal link between the alleged dumped imports and the injury suffered by the domestic industry as a whole.
- L. Magnitude of Injury and injury margin**
104. Since the injury to the domestic industry is not found to be on account of the dumped imports from the subject countries, determination of the injury margin is irrelevant. However, as per the Non-injurious price determined for the domestic industry on the basis of the relevant provisions of the Rules and taking into account the production loss during the POI, and the landed value of imports from the subject countries, the injury margins of imports work out as under:

Particulars	UOM	Japan	Thailand
Non Injurious Price	Rs./MT	***	***
Landed Price of dumped imports	Rs./MT	No Imports	1,01,241
Injury Margin	Rs./MT		***
	%		0-10%

105. Though, the weighted average landed price was marginally below the weighted average non-injurious price determined for the domestic industry, the weighted average selling price of the domestic industry was found to be above the non-injurious price.
106. The domestic industry as well as the opposing interested parties, in their post disclosure submissions, have raised certain issues regarding the determination of the non-injurious price. However, the Authority notes that the non-injurious price has been determined as per the consistent practice of the Authority in terms of the methodology in Annexure III of the AD Rules and taking into account the information provided by the domestic industry and therefore, no revision of the NIP is called for.

M. Likelihood of continuation of injury

107. The domestic industry has argued that the current price undercutting and/or the potential undercutting, based on third country exports from the subject countries would indicate that the goods will cause material injury to the domestic industry if the duties are revoked. The opposing interested parties have, on the other hand, argued that the injury has not been caused by the imports from the subject countries and the domestic industry is suffering on account of its internal problems. It has been argued that there is no likelihood of recurrence of dumping from the subject countries due to prior commitment of major suppliers in the subject countries for their own captive consumption and other committed buyers.
108. In its post disclosure comments the domestic industry has reiterated its stand and has argued that in case of expiry of existing duty, exporters from the subject country would further channelize their output in the Indian market, as they are already holding excessive capacities and are highly export oriented. It has been argued that the producer in Thailand are increasing its capacity. This excessive capacity would be used to increase its exports and India being large demand would be first choice for them. The imports are still continuing at dumping prices rather increased in post POI. Thus, existence of such a situation after imposition of anti-dumping duty gives a clear implication of likelihood of injury.
109. The opposing interested parties, in their post disclosure submissions, have argued that the post POI data does not indicate any significant increase in volume of imports from Thailand while import from Japan continues to be nil, though there is a significant demand supply gap arising out of closure of the plant of the domestic industry. The price level of imports from all sources shows a decline in prices because of the decline in raw material prices. It has been further argued that there is no likelihood of recurrence of dumping and resultant injury from Thailand due to prior commitment to buyers' major markets in third countries as well as for its own captive consumption.
110. As noted earlier there was no dumping of the subject goods from Japan during the POI and the dumping margin of imports from Thailand was marginally above *de minimis* during the POI. It was also noted that there is no imminent likelihood of intensified dumping from the subject countries, keeping in view the capacities and demand supply position of the major producers in those countries. The post POI data indicates that there is an increase in volume of imports to fill in the demand supply gap arising out of closure of the plant of the domestic industry. The price level of imports from all sources show a decline in prices apparently because of the decline in raw material prices.
111. Post POI data (Oct-March 2015) of the domestic productions shows that HOCL was out of production for the entire period but the other producer (SI Group) continued to operate at almost full capacity. Further the analysis in the previous section establishes that the production of HOCL has been suspended largely because of its internal problems arising out of non-availability of working capital to purchase raw materials and outstanding dues to its raw material supplier. Therefore, the question arises whether the Company would be in a position to revive its production if the duties are continued.

112. The examination of various factors and information available with the Authority indicates that without resolving the working capital and management issues the unit would not be in a position to revive production and sale, even if an antidumping duty protection is provided. The resumption of production, with certain understanding with the raw material supplier recently, is yet to stabilise. The impact of imports from various sources, including the subject countries during the POI, was negligible. Therefore, in the factual matrix of the case the Authority is of the view that though the injury to the industry as a whole is likely to continue it would not be on account of the dumped imports from the subject countries and continuation of the measure would be of no help in revival of HOCL unless other measures are put in place.

N. Indian Industry's interest and other issues

113. The purpose of imposing anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian domestic market. However, in the instant case one of the domestic producers have gone out of production because of factors other than dumped imports from the countries against which this review was conducted. The other domestic producer is not significantly affected during the period under review. There is significant demand supply gap in the domestic market which necessitates imports. Therefore, neither the interests of the domestic producers of the subject goods nor the interests of the user industry would be best served if the duties on the subject goods from the subject countries are extended by another period of five years.

O. Conclusion and Recommendations

114. The Authority initiated and conducted this review investigation in accordance with the Law and examined the current dumping, injury and causal links between dumping and injury to the domestic industry and likelihood of continuation or recurrence of dumping from the subject countries and consequent injury to the domestic industry in the event of withdrawal of duty. It has been established in the foregoing paragraphs that there was no dumping of the subject goods from Japan during the period under review. Dumping continued from Thailand but at a very low level. It was also found that though imports from Thailand may continue at the present level, and some imports may take place from Japan, if the duties are revoked, there is no imminent likelihood of recurrence of intensified dumping of the subject goods from the subject countries. It has also been established that though the domestic industry as a whole has suffered injury during the period of review, the injury suffered is on account of account of HOCL's performance due to factors other than the dumped imports from the subject countries. The performance of the other domestic producer is not significantly affected during the period of review and marginal decline, if any, cannot be attributed to the dumped imports as imports are taking place from other countries as well at similar price levels.
115. The examination also indicates that even if the duties are extended HOCL would not be able to revive its production to a level where it will be viable, unless other fundamental issues affecting the Company are addressed as a long term solution to the problems of the Company. Since one of the two domestic producers was out of production it has added to the demand supply gap in the country. Therefore, neither the interests of the domestic producers of the subject goods, nor the interests of the user industry would be best served if the duties on the subject goods from the subject countries are extended for a further period of five years.
116. Therefore, the Authority is of the view that there is no need for continued imposition of the duties on the import of the subject goods from the subject countries. Accordingly, the Authority does not recommend continuation of definitive anti-dumping duty on import of Phenol originating in or exported from Japan and Thailand, imposed vide Customs Notification No.120 /2010-Customs dated 1st December 2010.
117. Appeal against the orders of the Central Government that may arise out of the recommendations of the Designated Authority lies before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the relevant provisions of the Act.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority